A Daily News Magazine
इंदौर
बुधवार, 11 जून, 2025

सुबह सवेरे

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 10 अंक 241, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

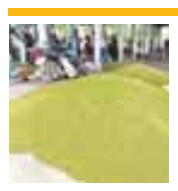

पड़ोसियों के जरिए भारत को घेर रहा है चीन!

पंकज श्रीवास्तव

चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत के पड़ोसी देशों में प्रभाव बढ़ाकर रणनीतिक घेराबंदी कर रहा है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते संबंध भारत की सुरक्षा पर क्या असर डाल सकते हैं?

भारत के पड़ोस में एक नई चुनौती उभर रही है, जो देश की सुरक्षा और कूटनीति के लिए गंभीर खतरा बन रही है। यह चुनौती है चीन की अपने पड़ोसियों के साथ बढ़ती नजदीकी। पाकिस्तान तो पहले से ही चीन का 'लौह मित्र' रहा है, लेकिन अब नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देश भी धीरे-धीरे चीन के प्रभाव क्षेत्र में आते दिख रहे हैं। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई के तहत भारी निवेश और रणनीतिक परियोजनाओं के जरिए भारत को क्षेत्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है। आखिर भारत अपने पड़ोसियों से क्यों दूर हो रहा है? क्या यह भारत की कूटनीति और विदेश नीति की असफलता नहीं है।

चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना यानी BRI दुनिया के 150 से अधिक देशों में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश कर रही है। इसका लक्ष्य सड़कों, रेल, बंदरगाहों और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए वैश्विक व्यापार और प्रभाव बढ़ाना है। भारत इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके पड़ोसी देश इस जाल में फंसते जा रहे हैं।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) BRI का हिस्सा है। यह 62 अरब डॉलर की परियोजना है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को गिलगित-बाल्टिस्तान के रास्ते चीन के शिनजियांग से जोड़ता है। भारत का कहना है कि यह गलियारा अवैध रूप से कब्जाए गए गिलगित-बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन चीन के लिए यह गलियारा सामरिक और आर्थिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि वह भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करता है। ग्वादर बंदरगाह में चीन का भारी निवेश है, जिसे भविष्य में सैन्य ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

भारत से दुश्मनी के चलते पाकिस्तान का चीन की ओर झुकाव स्वाभाविक लगता है, लेकिन नेपाल जैसे पारंपरिक मित्र का रुख बदलना भारत के लिए चिंता का विषय है। कभी भारत का सबसे करीबी पड़ोसी रहा नेपाल अब चीन की ओर झुक रहा है। 2015 में नेपाल के नए संविधान पर भारत के विरोध और कथित नाकेबंदी ने नेपाल को आर्थिक संकट में डाल दिया। नतीजतन, नेपाल ने चीन की ओर रुख किया। चीन ने नेपाल में ट्रांस-हिमालयन रेल परियोजना शुरू की है, जो तिब्बत के शिगात्से को काठमांडू से जोड़ेगी। इस 5.5 अरब डॉलर की परियोजना को 2027 तक पूरा किया जाना है, जिसे बाद में पोखरा और लुंबिनी तक विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा, चीन ने नेपाल में सड़कों, हाइड्रोपावर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क में 10 अरब डॉलर का निवेश किया है।

2020 में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर भारत के साथ विवाद बढ़ाया। साथ ही, चीन ने नेपाल के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति शुरू की है। 2019 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नेपाल यात्रा ने दोनों देशों के बीच 'रणनीतिक साझेदारी' को और मजबूत किया। भारत की सीमा से महज 700 किलोमीटर दूर काठमांडू है। लुंबिनी तो सीमा से सटा इलाक़ा है। यहाँ तक चीन की ट्रेन से पहुँच का मतलब समझा जा सकता है।

1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन हाल के वर्षों में स्थिति बदली है। शेख हसीना की सरकार के बाद बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने चीन के साथ सहयोग बढ़ाया है। 1 जून 2025 को ढाका में आयोजित चीन-बांग्लादेश निवेश और व्यापार सम्मेलन में 150 से अधिक चीनी निवेशकों ने हिस्सा लिया और 2 अरब डॉलर के नए निवेश की घोषणा की। चीन ने बांग्लादेश में पायरा कोयला पावर प्लांट और चट्टोग्राम बंदरगाह में भारी निवेश किया है। बांग्लादेश का कुल बाहरी कर्ज 101.4 अरब डॉलर है, जिसमें 14.8 प्रतिशत हिस्सा चीन का है। इसके अलावा, चीन ने बांग्लादेश को दो पनडुब्बियां भी बेची हैं, जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं।

भूटान भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है, लेकिन चीन यहाँ भी अपनी पैठ बना रहा है। 2017 का डोकलाम विवाद इसका उदाहरण है। डोकलाम भूटान में है, लेकिन यह भारत के सिलिगुरी कॉरिडोर (चिकन्स नेक) के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। चीन ने डोकलाम में सड़क निर्माण शुरू किया, जिसे भारत और भूटान ने संप्रभुता का उल्लंघन माना। 72 दिनों तक भारत और चीन की सेनाएँ आमने-सामने रहीं। हालाँकि दोनों पक्ष पीछे हटे, लेकिन चीन ने डोकलाम में सैन्य ढांचा बनाना जारी रखा।

2023 में भूटान और चीन ने सीमा वार्ता के लिए एक तीन-चरणीय रोडमैप पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत में चिंता बढ़ा दी। भारत और म्यांमार के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह और इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग में निवेश किया है। लेकिन म्यांमार की अस्थिरता और चीन के 1.5 अरब डॉलर के निवेश ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को कमजोर किया है। म्यांमार का कुल बाहरी कर्ज 10 अरब डॉलर है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है।

श्रीलंका में चीन की रणनीति को 'डेट ट्रैप डिप्लोमेसी' का उदाहरण माना जाता है। 2017 में श्रीलंका ने 1.2 अरब डॉलर का चीनी कर्ज न चुका पाने के कारण हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया। श्रीलंका का कुल बाहरी कर्ज 61 अरब डॉलर है, जिसमें 8.54 अरब डॉलर चीन का है। 2022 के आर्थिक संकट में भारत ने श्रीलंका को 4 अरब डॉलर की सहायता दी, लेकिन 2024 में बनी नई सरकार (NPP) ने चीन के साथ रक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाया। हंबनटोटा बंदरगाह, भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

चीन की रणनीति को 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' कहा जाता है, जिसके तहत वह ग्वादर, हंबनटोटा, क्याउकप्यू और चट्टगांव जैसे बंदरगाहों में निवेश कर भारत को समुद्री और स्थलीय मार्गों से घेर रहा है। यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।

भारत ने 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के तहत श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार में भारी निवेश किया है। उदाहरण के लिए, श्रीलंका को 4 अरब डॉलर की सहायता, मालदीव में 500 मिलियन डॉलर का निवेश और बांग्लादेश में 8 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन। लेकिन चीन का 48.1 अरब डॉलर का कर्ज भारत के 9 अरब डॉलर के निवेश पर भारी पड़ रहा है।

(सत्य हिंदी डॉट कॉम में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

चरण छूने योग्य नहीं, पूजनीय हैं वो पुरुष..
जिनके लिए प्रेम किसी वादे का बंधन नहीं,
बल्कि किसी की स्वतंत्रता की
रक्षा का संकल्प था।
जिन्होंने उसे खोकर भी
उसके लिए दुआ माँगनी नहीं छोड़ी,
क्योंकि मोहब्बत उनके लिए
स्वार्थ नहीं, पवित्रता थी।
जो हँसी-हँसी में सब कुछ सह गए,
ताकि कोई यह न कहे कि
प्रेम में पुरुष कमज़ोर हो गया।
वे कमज़ोर नहीं थे,
बल्कि इतनी शक्ति रखते थे कि
किसी की छवि को धुंधला न होने दिया।
वे पुरुष –
न लेखों में मिलते हैं, न मंचों पर चढ़ते हैं,
पर हर उस स्त्री की आत्मा में बसे होते हैं,
जिसने सच्चे प्रेम को एक बार जिया हो।
वे पुरुष, जो टूटे
पर अपनी टूटन से किसी और का
विश्वास न टूटने दिया।
जो चले गए
पर जाते-जाते भी आदर छोड़ गए।
क्योंकि उनके लिए प्रेम
किसी की बाहों में समा जाना नहीं था,
बल्कि उसकी गरिमा में चुपचाप शामिल रहना था।

– निशा शेखावत

सीएम यादव ने बताई मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियां, बोले–

11वें नंबर की अर्थव्यवस्था आज चौथे नंबर पर है

भोपाल (नप्र)। केन्द्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम डॉ. मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कांग्रेस के शासन का जिक्र करते हुए कहा- एक वो दौर था, जब करीब 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। लेकिन, गरीबों के बारे में नहीं सोचा। हर घर को शौचालय हो, नल से जल की बात हो या गैस के कनेक्शन की बात हो। कांग्रेस ने कभी इस दिशा में नहीं सोचा।

मोदी ने अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंचाया– सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा-1947 की बात करें तो चैट जीपीटी या गूगल से देखें तो अर्थव्यवस्था के मामले में भारत दुनिया में 15वें नंबर पर था। जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो उस समय भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर था। हम संयुक्त गठबंधन की सरकार के बीच परमाणु बम का उदाहरण ले सकते हैं, जो प्रयोग अटल जी ने किया था। 2014 के पहले मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, उसके पहले वे वित्त मंत्री थे।

मोदी जी के कामों में सबसे बड़ी बात है कि नेतृत्व करने वाला हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहे। सरकार के मामले में तुष्टिकरण समाप्त करने के लिए जनता के लिए कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। मोदी जी ने न जाने कितने फैसले लिए।

370 के मामले को लेकर राजीव गांधी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे– सीएम ने कहा- स्टार्टअप की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है लेकिन हम सब लाइन से देखें तो 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर राजीव गांधी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे।

मोदी ने मुस्लिम बहनों की जिंदगी बदली– मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी करनी है, बदलना है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, तो आप केवल दो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें। लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत क्या होती है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट तो करेगी लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए था। जहां तीन तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। अपने मध्य प्रदेश के इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में और उसके उलट राजीव गांधी की सरकार ने फैसला बदल दिया था।

सीएम ने कहा- आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर हैं और इस बात के गवाह हैं। जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था। उनके स्वयं के शब्दों में आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी क्या है? मोदी जी ने कहा हम हिंदू, मुस्लिम में भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे हिंदू बहनों की जिंदगी में भी मदद करेंगे। मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी बदलाव लाना है। तीन तलाक के कानून से उनके उनकी जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है तो तीन तलाक को बदलने की हिम्मत दिखाने का काम भी किसी ने किया तो वह मोदी जी के सरकार ने किया।

मोदी सरकार के 11 सालों के कामों पर बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

'विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम.. मोदीज भारत @2047', मुख्यमंत्री ने किया संदर्भ पुस्तक का विमोचन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में 'विश्व गुरु की ओर बढ़ते कदम.. मोदीज भारत @2047' संदर्भ पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन के अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट सहित पुस्तक के संकलन कर्ता श्री ऊनमीत सिंह नारंग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश का रक्षा क्षेत्र सुदृढ़ हुआ है। वर्ष 2014 के मुकाबले भारत में स्वदेशी रक्षा उत्पादन 174 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 27 हजार 434 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है, वहां भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक (डिफेंस एक्सपोर्टर) बन गया है। यह निर्यात 100 से अधिक देशों तक फैला हुआ है, जो 2014 में लगभग शून्य था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से रक्षा से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने श्रेष्ठता सिद्ध की है और देश को सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में नई वैश्विक पहचान मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रक्षा गलियारों में 50 हजार 83 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत अपनी निर्माण क्षमताओं को बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के समक्ष अपना पराक्रम दिखाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शी नीतियों से जम्मू-कश्मीर में 2023 से पत्थरबाजी की एक भी घटना सामने नहीं आई है।

हत्या के बाद इंदौर आई थी सोनम

- 'ऑपरेशन हनीमून' में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा

कार से वाराणसी पहुंची, फिर गाजीपुर पहुंचकर किया फोन

इंदौर (एजेंसी)। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम रघुवंशी पति की हत्या के बाद 25 मई को शिलॉन्ग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची थी। इंदौर में वह अपने प्रेमी राज कुशवाह से मिली थी और उसके किराए के कमरे में रुकी थी। उसे एक ड्राइवर ने वाराणसी में ड्रॉप किया था, जहां से वह गाजीपुर पहुंची थी। शिलॉन्ग एसपी विवेक स्येम ने इस बात को कन्फर्म किया है। उधर, मेघालय पुलिस इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी (29) की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी सोनम को लेकर पटना एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। टीम पहले कोलकाता पहुंचेगी फिर गुवाहाटी होते हुए शिलॉन्ग पहुंचेगी। वहीं, इंदौर में क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस की एक टीम मामले के आरोपी विशाल को लेकर उसके घर पहुंची। यहां सर्चिंग के दौरान वारदात के समय पहने गए कपड़े जब्त किए गए। क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद्र यादव ने बताया कि राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने ही किया था।

ओडिशा में रेप के आरोपी की हत्या, शव भी जलाया

- जंगल से हड्डियां और राख बरामद, 8 महिलाओं सहित 10 गिरफ्तार

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के गजपति जिले में 60 साल के रेप के आरोपी की हत्या करके शव जला दिया गया। पुलिस ने 10 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 8 महिलाएं और दो पुरुष हैं। पुलिस ने गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र के पास एक पहाड़ी से मृतक की हड्डियां और राख बरामद की। पुलिस ने बताया कि, जिन महिलाओं को पकड़ा गया है, वे सभी यौन शोषण का शिकार हुईं थीं। 52 साल की विधवा के साथ रेप से गुस्सा बढ़ा पुलिस ने बताया कि, जिस व्यक्ति को मारा गया है वह काफी समय से महिलाओं का शोषण कर रहा था।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय

प्रदेश की 20 हजार 600 सुदूर बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने 21 हजार 630 करोड़ रूपये की मंजूरी

- मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत 30 हजार 900 किलोमीटर सड़क का होगा निर्माण
- बढ़ी तबादला अवधि, 17 जून तक होंगे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर बसाहटों मजरा/टोला/धोनी/पुरा इत्यादि को बारहमासी सम्पर्कता प्रदान करने 21 हजार 630 करोड़ रूपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पहले चरण एवं वित्तीय वर्ष 2030-31 से 2034-35 तक दूसरे चरण में कुल अनुमानित 30 हजार 900 कि.मी. मार्ग का निर्माण होगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जायेगा। योजना के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को निर्णय लिये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।

स्वीकृति अनुसार न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र, जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व से बारहमासी सड़क न हो, को बसाहट के अंतर्गत लिया जायेगा। इसके लिए बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जायेगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीणजनों की स्थानीय आवश्यकता जैसे - सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर बसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंतिम प्राथमिकता सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन किया जायेगा। योजना अंतर्गत 20 हजार 600 बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 30 हजार 900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

प्रदेश के बाहर से आयातित तुअर पर मंडी फीस से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय– मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में तुअर दाल उद्योगों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश में बाहर से आयातित तुअर पर मंडी शुल्क से पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। छूट दिए जाने से प्रदेश में तुअर दाल की पर्याप्त उपलब्धता होगी। साथ ही परिवहन बढेगा और रोजगार में वृद्धि होगी।

मंत्रि-परिषद द्वारा झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में कामकाजी महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से (स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट) 2024-25 योजना अंतर्गत स्वीकृत 350 सीट्स की क्षमता वाले 4 वर्किंग वूमन हॉस्टल के निर्माण का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है।

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 11 जून 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

नौतपा जैसी गर्मी, सड़कों में बरस रही है आग

● 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी,बारिश की संभावना नहीं ● 47.3 डिग्री के साथ राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के उत्तरी राज्यों में तेज गर्मी का दौर जारी है। देश के 6 राज्यों के 18 शहरों का तापमान सोमवार को 45 डिग्री के ऊपर रहा। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा शामिल हैं। राजस्थान का श्रीगंगानगर 47.3 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मंगलवार को भी हीट वेव और तेज गर्मी की चेतावनी है। दिल्ली में आज भी तापमान 45 डिग्री के पास जा सकता है। राज्य में अगले दो दिन के लिए हीट वेव-गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में तेज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही में है। हरियाणा में भी सोमवार को तापमान 45 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर गया। प्रदेश में सिरसा 46.4 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहा।

असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्य के 1.63 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में इस साल बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं बह रही है। आंधी-बारिश का दौर थमते ही मध्य प्रदेश में नौतपा जैसी गर्मी है। भोपाल, ग्वालियर समेत कई शहरों में सूरज के तेवर तीखे हैं। सोमवार को 7 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार रहा।

पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा भारत

● दुश्मनों से मिलाया हाथ,जयशंकर का प्लान उड़ा देगा पड़ोसी देश के होश

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूरोप के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पहलगाम में आतंक हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया पूरी दुनिया देख चुकी है। आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर अडिग है। जयशंकर ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक प्लान भी बना लिया है। उन्होंने मध्य एशियाई देशों का आतंक पर नेटवर्क बनाने की बात की

इसके बावजूद अगर पाकिस्तान और उसके यहां पल रहे आतंकी भारत के खिलाफ कुछ भी गलत करते हैं तो इस बार उनकी तबाही तय है। एक फ्रेंच अखबार ली फिगारो को दिए साक्षात्कार में जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत है। जयशंकर ने मध्य एशियाई देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। यह मुलाकात भारत-मध्य एशिया वार्ता से पहले हुई। इस बैठक में आतंकवाद, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर बात हुई। भारत और मध्य एशियाई देश मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे।

डॉलर पर पड़ेगी चोट, अमेरिका का वर्चस्व टूटेगा

जयशंकर ने आगे कहा-मैं निश्चित रूप से उन कदमों का समर्थन करूंगा जो हम अपने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार के आपसी निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत और मध्य एशियाई देश अपनी-अपनी मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी। भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार बढ़ने से दोनों क्षेत्रों को फायदा होगा। भारत को मध्य एशिया से ऊर्जा और खनिज मिल सकते हैं। वहीं, मध्य एशियाई देशों को भारत से मिल सकते हैं। कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार और आसान हो जाएगा। भारत चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इससे पाकिस्तान को दरकिनार किया जा सकेगा। इससे पहले दिसंबर, 2022 की बात है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में पहली मध्य एशियाई देशों के अपने समकक्षों के साथ एक मीटिंग की थी। उस वक्त डोभाल ने कहा था कि मध्य एशिया भारत का विस्तारित पड़ोस है। भारत के लिए एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध मध्य एशिया साझा हित में बेहद जरूरी है।

सामाजिक भेदभाव का नया जरिया बन गया है इंटरनेट

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में इंटरनेट समाज को विभाजन की ओर ले जा रहा है।

उन्होंने न्याय वितरण प्रणाली में टेक्नोलॉजी की दोहरी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दौर में इंटरनेट सामाजिक भेदभाव का एक नया उपकरण बन गया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपकरणों और डिजिटल साक्षरता तक समाज के सभी वर्गों की असमान पहुंच से हाशिए पर पड़े समुदायों का बहिष्कार हो सकता है, जो पहले से ही न्याय के लिए कई किस्म की बाधाओं का सामना कर रहे हैं। सीजेआई गवई ने कहा, वास्तविकता में न्याय प्रदान करने की दिशा में पहुंच और समावेशन के आधार पर टेक्नोलॉजी को डिजाइन का आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल उपकरणों को न्यायिक तर्क की सहायता करनी चाहिए, न कि उसे रिप्लेस करना चाहिए।

जी-7 से पहले साइप्रस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी

● पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को देंगे सख्त संदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस भी जाएंगे। ऐसा करने वाले वह देश के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। साइप्रस के बाद पीएम मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा जाएंगे। फिर स्वदेश लौटते समय क्रोएशिया भी जाएंगे। भारत यूरोप में अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है और उनकी इन यात्रा कार्यक्रमों से भी यही बात निकल कर आ रही है। साइप्रस और क्रोएशिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। साइप्रस अगले साल के पहले छह महीनों के लिए यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता भी करेगा। पहले पीएम मोदी को पिछले महीने क्रोएशिया जाना था। इसके साथ वे नीदरलैंड और नॉर्वे भी जाने वाले थे।

● **साइप्रस और ग्रीस आतंकवाद-कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ-** साइप्रस और ग्रीस दोनों ही देशों ने आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार साइप्रस ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। इनमें यूएनसी में भारत का चुनाव, भारत-अमेरिका परमाणु समझौता, एनएसजी सदस्यता और 1998 के परमाणु परीक्षण शामिल हैं। ऐसे में साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत का मजबूत रिश्ता तुर्की को एक संदेश है। भारत यह दिखाना चाहता है कि उसके दोस्त भी हैं और वह अकेला नहीं है।

भारत के खिलाफ खतरनाक प्लान पर काम कर रहा चीन

नेपाली लड़कियों से शादी,सीमा पर दुकानें बनाकर रच रहा साजिश

अररिया (एजेंसी)। भारत नेपाल की खुली सीमा का बड़ा भू-भाग तराई अर्थात मैदानी इलाका है। नेपाल के अधिकांश बड़े उद्योग-धंधे और कारोबार तराई क्षेत्र में हैं। नेपाल-भारत के साथ चीन की सीमा से लगती है। भौगोलिक आधार पर भारत और चीन के मध्य नेपाल है और यह आकृति सैंडविच के समान है। नेपाल में कुछ दशकों में चीन का हस्तक्षेप बढ़ा है। चीन के कई बड़े प्रोजेक्ट नेपाल में स्थापित हो रहे हैं। नेपाल की बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर चीन के प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख परियोजनाओं में वेस्ट सेटी बांध परियोजना, जो परियोजना वेस्ट सेटी नदी पर है। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल के लिए ऊर्जा उत्पादन में चीन की ओर से स्थापित की जा रही है। पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए पोखरा हवाई अड्डा प्रोजेक्ट है। बिजली उत्पादन के लिए ऊपरी त्रिशूली जलविद्युत

परियोजना त्रिशूली नदी पर स्थापित की जा रही है। ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क परियोजना नेपाल और चीन के बीच बुनियादी ढांचे और व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए है और यह परियोजना चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल का हिस्सा है।

मुआवजा नहीं मिलने पर हाईवे पर कब्जा

● ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़े कर दीवार बनाने लगे,पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया

कुरुक्षेत्र (एजेंसी)। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मंगलवार सुबह कुछ लोगों ने पिहोवा में स्टेट हाईवे नंबर 6 पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली अड़ाकर दीवार बनानी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कब्जा करने वाले नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद हाईवे पर रखी ईंटें उठाई गईं और ट्रैफिक चालू कराया गया। किसान का आरोप है कि एजेंसी ने सन 1987 में उसकी जमीन पर सड़क बना दी। मैं 3 बार कोर्ट से केस जीत चुका हूं। अभी तक मुझे इसका मुआवजा नहीं मिला है। इसलिए परेशान होकर कब्जा करने का फैसला लेना पड़ा।

पहली बार मनरेगा में खर्च की लिमिट तय

● केंद्र सरकार ने लगाई पाबंदी, ग्रामीण रोजगार पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर के ग्रामीण इलाकों में श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने वाली महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) पर पहली बार केंद्र सरकार ने खर्च सीमा की पाबंदी लगाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत होने वाले खर्च को कुल वार्षिक आवंटन का 60 फीसदी तक सीमित कर दिया है। अब तक इस योजना में खर्च की कोई सीमा तय नहीं थी और यह मांग के आधार पर संचालित योजना रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को सूचित किया है कि अब इस योजना के तहत होने वाले खर्च को मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना के तहत लाया जाएगा, जो एक खर्च पर नियंत्रण का एक तरीका है। हालांकि, इस योजना को अब तक इस तरह के नियंत्रण उपायों से छूट मिली हुई थी। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों के तहत कैश फ्लो और गैर जरूरी उधारी को कम करने और उसे नियंत्रित करने के लिए 2017 में मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना की शुरुआत की थी लेकिन मनरेगा स्कीम को इससे बाहर रखा था। ऐसा कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को निर्देश दे दिए थे कि वह मनरेगा को भी मासिक/त्रैमासिक व्यय योजना ढांचे में शामिल करे। पिछले महीने 29 मई को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बावत ग्रामीण विकास मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर 60 फीसदी खर्च की सीमा तय करने के फैसले से अवगत करा दिया है।

शहीद एसीपी का हुआ अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि

● पत्नी ने रोते हुए सैल्यूट किया,नक्सल ऑपरेशन चीफ बोले-बलिदान बेकार नहीं जाएगा

रायपुर (एजेंसी)। सुकमा नक्सल आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए एसीपी आकाश राव का अंतिम संस्कार किया गया। रायपुर के महादेवघाट मुक्तिधाम में बेटे ने मुखाग्नि दी। परिजन, पुलिस

और प्रशासनिक अफसरों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान वहां मौजूद नक्सल ऑपरेशन के चीफ आईपीएस विवेकानंद ने कहा कि आकाश का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। इससे पहले शहीद गिरिपुंजे को माना पुलिस बटालियन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पत्नी ने रोते हुए सैल्यूट किया, वहीं मां-पिता बिलखते रहे। सीएम साय उनके मंत्रियों और अफसरों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा के दौरान रास्ते भर जब तक सूरज चांद रहेगा, आकाश तेरा नाम रहेगा के नारों की गूंज रही। अंतिम यात्रा में कलेक्टर के साथ कई अफसर और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

अब सेना को मिलेगा एक और नया एयर डिफेंस सिस्टम

● क्यूआर-एसएएम की खासियत मूविंग टारगेट तबाह करना

डीआरडीओ से 30 हजार करोड़ में 3 रेजीमेंट खरीदी जाएंगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना को जल्द ही नया एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। डिफेंस के अधिकारियों के मुताबिक- रक्षा मंत्रालय चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनाती के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तीन रेजिमेंट खरीदने को लेकर विचार कर रहा है। ये डील 30 हजार करोड़ की होगी। एसएएम दिन और रात दोनों समय कारगर है, इसकी सफल टेस्टिंग भी की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक, इस डिफेंस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। एसएएम सिस्टम में मूविंग टारगेट खोजने, ट्रैक करने और कम समय में फायर करने की कैपेसिटी है। लगभग 30 किमी की रेंज के साथ डीआरडीओ मीडियम से कम डिस्टेंस में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और आकाश जैसी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करेगी। इस डिफेंस सिस्टम के सेना में शामिल करने के लिए काउंसिल की बैठक जून के चौथे सप्ताह में हो सकती है।

अभी भारत के पास आकाशतीर, एस-400 सिस्टम और आयरन ड्रोन जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। इन्होंने ही भारत-पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई तक चले संघर्ष के दौरान तुर्किस ड्रोन्स को खत्म किया था।

मुझे आंसू आने लगे, क्या सचमुच वो दिन आ गया

कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे फारुक अब्दुल्ला बोले-माता ने बुलाया है

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया प्रमुख फारुक अब्दुल्ला ने आज मंगलवार को श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा की। इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है कि यह वंदे भारत ट्रेन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। फारुक अब्दुल्ला नौगाम (श्रीनगर) रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन में चढ़ें थे और उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक का सफर किया। इस दौरान जब फारुक अब्दुल्ला मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि चिनाब पुल पार करते हुए उनकी आखें नम हो गईं। बता दें कि कटरा-श्रीनगर रेल लिंक के जरिए कश्मीर घाटी को पहली बार पूरे देश से जोड़ा गया है। कटरा-श्रीनगर रेल लिंक उधमपुर-श्रीनगरबारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

लॉस एंजिलिस हिंसा ने ट्रंप के 'सपने' को किया चकनाचूर

● सुपर पॉवर का बुरा हाल, 2000 नेशनल गार्ड्स और भेजे ● अब कुल 4000 की तैनाती,700 मरीन कमांडों भी तैनात

लॉस एंजिलिस (एजेंसी)। अमेरिकी राज्य कैलीफोर्निया के लॉस एंजिलिस में 4 दिनों से जारी हिंसा में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है। यह हिंसक प्रदर्शन अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे हैं। इस प्रदर्शन को काबू करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने 2000 नेशनल गार्ड्स और तैनात करने का फैसला किया है, जिससे इनकी कुल संख्या 4000 हो जाएगी। इसके अलावा 700 मरीन कमांडों भी तैनात करने का फैसला किया है। यह नेशनल गार्ड के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। ये मरीन जवान दक्षिण कैलीफोर्निया के ट्वेंटी नाइन पाम्स बेस से आ रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि यह तैनाती अगले कुछ घंटों में हो सकती है। इससे पहले ट्रम्प नें फैली हिंसा और तोड़फोड़ के बाद वहां तैनात किए गए नेशनल गार्ड के जवानों की तारीफ भी की।

बहन बोली- राजा की हत्या के बाद रोया था राज

सोनम की सलामती के लिए मंदिर जाता, आखिरी बार घर आया तो नए कपड़े पहने

इंदौर (एजेंसी)। राज भैया आखिरी बार रविवार सुबह घर आए थे। यहां उसने नए कपड़े पहने। मुझसे कहा कि सफेद शर्ट और जींस दे दो, मंदिर जाना है। इसके बाद वह मंदिर चला गया। रात करीब 11 बजे भैया से सामान्य बात हुई थी। बस इसके बाद से ही भाई से अब तक कोई बात नहीं हुई। मेरा भाई बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। राज कुशवाह की नाबालिग बहन ने रोते हुए ये बात कही। उसने कहा कि जब से भाई का नाम इस मर्डर केस में आया है, मां चुन्नी बाई (52) बदहवास है। छोटी बहन की तबीयत भी खराब हो गई है। वो उठ भी नहीं पा रही है। उसने कहा, हम सोनम से एक बार ही मिले थे। वो ऐसा नहीं कर सकती। गरबे के समय सोनम और उसकी टीम से मुलाकात हुई थी। इसके बाद हम नहीं मिले। सोनम कभी घर पर नहीं आई। मेरा भाई कभी भी इतना बुरा नहीं सोच सकता।

मकान मालिक बोले- मोहल्ले में सिर झुकाकर चलता था

राज के मकान मालिक ने बताया, करीब 10 साल से राज और उसके परिवार को जानता हूं। राज की तीन बहनें हैं, एक बहन गांव में और दो साथ में रहती हैं। कोरोनाकाल में उसके पिता की मौत हो गई थी। तब हम सभी ने चंदा कर उनका

अंतिम संस्कार करवाया था। वो लड़का आज तक सिर उठाकर मोहल्ले में नहीं चला। सुबह काम पर जाता और शाम को घर आ जाता था। उसे देखकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो इस तरह का कदम उठा सकता है।

बहन बोली- सोनम को दीदी कहता था राज

बहन ने बताया, भाई दो-ढाई साल से काम कर रहा था। उसे कौन फंसा रहा है, हमें नहीं मालूम। हत्या के पहले और बाद में भैया बिल्कुल नॉर्मल रहा। राजा रघुवंशी की हत्या का पता चला तब भैया बहुत रो रहे थे। मां से कहा था कि राजा का परिवार बुरी तरह परेशान है।

मां बदहवास

राज की मां एक ही बात कह रही है, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो मेरा इकलौता बेटा था। दो बेटियों में छोटी बेटी बार-बार बेहोश हो रही है। मैंने भी तीन दिन से पानी नहीं पिया। मेरे पति शांत हो गए, अब कोई मेरे आगे पीछे नहीं है। वह इतना भोला है कि जिसके भी पैर में जूते-चप्पल नहीं होते तो खुद अपने उतारकर दे देता था। वह नंगे पैर घर आता तो मैं चिल्लाती थी। उसे कव्तफ्थी कि खाना नहीं दूंगी, चप्पल कहां से लाऊं, पैसे नहीं है मेरे पास। सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था, वहीं पर सोनम भी काम करती थी। अब दोनों एक जगह काम करते हैं तो बातचीत तो होती ही है। उसे झूठा फंसा दिया ॥ राज ने अपनी दोनों बहन और मां को पहले ही उत्तरप्रदेश में कानपुर के पास रामपुर स्थित पैतृक गांव भेज दिया था। 8 दिन पहले ही दोनों लौटी हैं। विशाल ने भी अपने माता-पिता को गांव भेज दिया था।

राजा के अंतिम संस्कार में राज भैया शामिल हुए थे। हमारा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। वह तो सोनम दीदी की सलामती के लिए घर के मंदिर में रोज दुआ करता था। रोता भी था। कहता था कि राजा भैया की तो लाश मिल गई, लेकिन दीदी कैसी होगी। वे राजा की शव यात्रा में भी गए थे। वहां से लौटकर दो घंटे तक रोए। बोले कि लुटेरों ने ऐसी हालत कर दी कि राजा का चेहरा भी नहीं देख पाया।

विशाल-आकाश राज की बहनों के राखी भाई

बहन बोली, मैं और मेरी छोटी बहन विशाल (विक्की) और आकाश को राखी बांधते थे। वे हमें छोटी बहन जैसा ही रखते थे। बाकी दो और कौन लोग हैं, मैं नहीं जानती। सोनम से हम इतना नहीं मिले कि उन्हें ज्यादा जान सकें, पर वो ऐसा न कर सकती है ना करवा सकती है। सोनम का फोन आता था, गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है, इतनी बात करके फोन काट देती थी। राज भैया हमेशा सोनम को दीदी कहते थे। मेरी मम्मी तो कभी सोनम से मिली भी नहीं। वह केवल एक बार ही हमारे घर आई है।

सोनम की शादी में नहीं गया था राज

बहन ने बताया कि सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। इसी दिन 11 मई 2020 को हमारे पिता जी रामनजर सिंह की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई थी। इस कारण हम इस दिन को किसी भी तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। इसलिए राज उस दिन सोनम की शादी में नहीं गया था।

कांग्रेस 11 जुलाई को मनाएगी 'फेंकू दिवस'

मोदी सरकार की नीतियों को लेकर करेंगे प्रदर्शन, बीजेपी करेगी प्रोफेशनल मीट

इंदौर (एजेंसी)। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भाजपा 11 जुलाई को इंदौर में 'संकल्प से सिद्धि' अभियान के तहत विभिन्न आयोजनों की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस उसी दिन केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 'फेंकू दिवस' मनाएगी। शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कांग्रेस 11 जून को सुबह 9 बजे गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के नीचे यशवंत रोड पर 'फेंकू दिवस' मनाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर प्रतीकात्मक रूप से 'फेंकू मिठाई' का वितरण किया जाएगा। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि हाल ही में प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ केंद्र की जनविरोधी नीतियों, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता का ध्यान आकर्षित करेगी।

बीजेपी करेगी प्रोफेशनल मीट

दूसरी ओर, भाजपा 11 जुलाई को 'प्रोफेशनल मीट' का आयोजन करेगी, जिसमें शहर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, एनजीओ प्रतिनिधि और अन्य वर्गों के लोग शामिल होंगे। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि पार्टी मंडल स्तर पर सम्मेलन, वार्ड स्तर पर चौपाल और पौधरोपण जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। मिश्रा के मुताबिक, इन आयोजनों के माध्यम से मोदी सरकार की विकास योजनाओं और 11 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी।

भस्म आरती दर्शन

त्रिपुण्ड धारी भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक पूजन और भस्म अर्पित कर राजा स्वरूप श्रृंगार

उज्जैन (एजेंसी)। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार तड़के भस्म आरती के दौरान मंदिर के कपाट खोले गए। सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन कर घंटी बजाकर भगवान से आज्ञा लेकर सभा मंडप वाले चांदी के पट खोला गया। गर्भगृह के पट खोलकर पुजारी भगवान का श्रृंगार उतार कर पंचामृत पूजन के बाद कर्पूर आरती की। त्रिपुण्ड धारी भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन और भस्म अर्पित कर राजा स्वरूप श्रृंगार किया गया। नंदी हाल में नंदी जी का स्नान, ध्यान, पूजन किया गया। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद दूध,दही,घी,शक्कर, शहद फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। भगवान महाकाल का रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट भांग चन्दन ड्रायफ्रूट और भस्म चढ़ाई गई, शेषनाग का रजत मुकुट रजत की मुण्डमाल और रुद्राक्ष की माला के साथ-साथ सुगन्धित पुष्प से बनी फूलों की माला धारण की भगवान महाकाल ने। फल और मिष्ठान का भोग लगाया। झांझ, मंजीरे, डमरू के साथ भगवान महाकाल की भस्म आरती की गई। भस्म आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। महा निर्वाणी अखाड़े की और से भगवान महाकाल को भस्म अर्पित की गयी। मान्यता है की भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार रूप में दर्शन देते है।

पीथमपुर में साक्षरता अभियान की शुरुआत

13 हजार निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य, अगस्त में होगी परीक्षा

पीथमपुर (एजेंसी)। पीथमपुर के शासकीय बालक हाई सेकंडरी स्कूल सागौर में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रशिक्षण किया गया। यह प्रशिक्षण राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश और कलेक्टर के आदेश पर 10 जून को हुआ। कार्यक्रम में जनशिक्षकों और संकुल सह समन्वयकों को निर्देश दिए गए। उन्हें 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर लोगों का सर्वे करना है। अक्षर साथियों की मदद से नियमित कक्षाओं का संचालन कर निरक्षरों को साक्षर बनाया जाएगा। जिला सह-समन्वयक एफ.एस. जगदाले ने सभी ब्लॉकों को कार्य की जानकारी दी। सर्वे 15 जून तक पूरा करना है। इसकी जानकारी अगली टीएल बैठक में कलेक्टर को दी जाएगी। अभियान के तहत 13,000 निरक्षरों को चिह्नित करने का लक्ष्य है। नवसाक्षरों की परीक्षा अगस्त में होगी। साक्षर होने वालों और अक्षर साथियों को सामाजिक जन चेतना केंद्र पर प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षण में सागौर संकुल प्राचार्य रमेश डावर, बीएसी शेखर त्रिवेदी, जनशिक्षक प्रहलाद सिंह सोलंकी, चरण चौधरी और संकुल सह समन्वयक संतोष चौहान एवं शुभम जैन मौजूद रहे।

इंदौर बायपास पर ट्रक से टकराई कार

जलगांव से खाटूश्याम जा रहे थे युवक, पुलिसकर्मी सहित 6 घायल

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में इंदौर-मुंबई बायपास पर देर रात एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार छह लोग घायल हो गए। इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जिसने रास्ते में युवकों से लिफ्ट ली थी। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से रात में ही उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। तेजाजी नगर पुलिस के अनुसार दुर्घटना रात करीब 2 बजे चमेली देवी स्कूल के पास हुई। कार और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार गणेश पुत्र शांताराम (निवासी शिवखेड़ा, जलगांव), सचिन पुत्र बसंत, मयूर पुत्र युवराज, गजानंद पुत्र कौशल, संजय पुत्र रामकृष्ण और खंडवा पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिसकर्मी शाहिद मिर्जा घायल हुए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि सभी युवक जलगांव से खाटूश्याम दर्शन के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में खंडवा के पुलिसकर्मी शाहिद मिर्जा को उन्होंने लिफ्ट दी थी। शाहिद भी उसी कार में सवार था और हादसे में घायल हुआ है। पुलिस ने ट्रक और कार दोनों को जब्त कर लिया है। ट्रक ड्राइवर की पहचान की जा रही है।

एमपीएल में इंदौर पिंक-पैंथर्स का पहला मैच 14 जून को

फ्रेंचाइजी मोयरा ग्रुप के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से दो रॉ टैलेंट को मौका, वेंकटेश करेंगे कप्तानी

इंदौर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश प्रीमियर लीग-2025 (एमपीएल) के सीजन-2 के लिए मोयरा ग्रुप की फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम 'इंदौर पिंक पैंथर्स' नए जोश और रणनीति के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। इस बार टीम की कमान भारतीय टीम के उभरते ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को सौंपी गई है। पिछली बार टीम का नेतृत्व रजत पाटीदार ने किया था। ग्वालियर में एमपीएल-2 की शुरुआत 12 जून से हो रही है। जो 24 जून तक चलेगा। पहले यह टूर्नामेंट 27 मई से इंदौर में होना था। लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' और आईपीएल कार्यक्रम में हुए बदलावों और मानसून के कारण आयोजन स्थल और तारीखों में संशोधन किया गया है। इंदौर पिंक पैंथर्स की 18 सदस्यीय टीम में कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें कप्तान वेंकटेश अय्यर, कुलवंत खेजरोलिया, अक्षत रघुवंशी, अर्पित गौड़, राहुल चंद्रोल, मिहिर हिरवानी, और विक्रांत सिंह

भदौरिया प्रमुख हैं। एमपीएल 2025 में इंदौर पिंक पैंथर्स की पहली भिड़ंत 14 जून को जबलपुर रॉयल लायंस से होगी।

विमल तोड़ी बोले -इंदौर की फ्रेंचाइजी हमारे लिए गर्व की बात- मोयरा ग्रुप के फाउंडर और चेयरमेन विमल तोड़ी ने कहा कि इंदौर की फ्रेंचाइजी हमारे लिए केवल गर्व की बात नहीं, बल्कि यह हमारी खेलों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। इंदौर पिंक पैंथर्स के जरिए हम युवा खिलाड़ियों को एक सशक्त मंच देना चाहते हैं, ताकि वे राज्य और देश का नाम रोशन कर सकें। हमें विश्वास है कि यह टीम न केवल मैदान पर शानदार प्रदर्शन करेगी, बल्कि प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में भी जगह बनाएगी। मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाश तोड़ी ने कहा इंदौर पिंक पैंथर्स में युवा ऊर्जा और अनुभवी सोच का बेहतरीन संगम है। हमारा चयन सिर्फ नाम के आधार पर नहीं, बल्कि जज्बे, प्रतिभा और टीम भावना को ध्यान में रखकर किया गया है।

हमारी टीम क्रिकेटिंग टैलेंट को पहचान-प्लेटफॉर्म देने का मिशन- जैन

इंदौर पिंक पैंथर्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट संदीप जैन ने कहा इंदौर पिंक पैंथर्स सिर्फ एक टीम नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के क्रिकेटिंग टैलेंट को पहचान और प्लेटफॉर्म देने का एक मिशन है। हमारा उद्देश्य ट्रॉफी जीतने से कहीं बड़ा है।

मेट्रो को अक्टूबर तक रेडिसन चौराहा तक चलाने की तैयारी

इंदौर (एजेंसी)। 6 किमी के एलिवेटेड कॉरिडोर पर मेट्रो के कमर्शियल रन के बाद अब अक्टूबर 2025 तक इसे रेडिसन चौराहा तक चलाने की पूरी तैयारी है, लेकिन अब तक पार्किंग का कोई प्लान तैयार नहीं हो पाया है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जिला प्रशासन व नगर निगम को कई बार चिट्ठी लिखकर जगह मांग चुका है, लेकिन पार्किंग की जगह ढूंढना चुनौती बना हुआ है। चूंकि प्रतिदिन 15 हजार से ज्यादा लोग मेट्रो में सफर करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसलिए अब पार्किंग के लिए स्थान तय करना जरूरी हो गया है। सूत्रों का कहना है, समस्या यह आ रही है कि जिन सघन इलाकों से मेट्रो ट्रेन गुजरेगी, वहां पर एक से डेढ़ एकड़ क्षेत्रफल वाली बड़ी सरकारी जमीनें उपलब्ध नहीं हैं। आसपास भी रहवासी और कमर्शियल इलाका विकसित हो गया है।

मेट्रो को फीडर चाहिए- मेट्रो को फीडर चाहिए, लेकिन शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं है। इसलिए संभावना इस बात की ज्यादा है कि लोग निजी वाहनों से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचें। ऐसे में गाड़ियों को खड़ी करने की व्यवस्था जरूरी होगी। हालांकि निगम प्रशासन कनेक्टिविटी के लिए बसों व ई-रिक्शा को इंटीग्रेटेड करने की बात कह रहा है पर अभी रूट प्लान तैयार नहीं हो पाया है।

दो घंटे छात्रों का हंगामा

बोले- एमबीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा आगे बढ़ाई जाए, डीएवीवी का इनकार

इंदौर (एजेंसी)। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के नालंदा कैंपस में सोमवार को छात्रों ने दो घंटे तक हंगामा किया और एमबीए सेकंड सेमेस्टर की 14 जून से शुरू होने वाली परीक्षाएं आगे बढ़ाने की मांग की। छात्रों ने कहा कि किसी भी स्थिति में परीक्षा दस दिन से दो हफ्ते आगे बढ़ाई जानी चाहिए। छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा और कहा, तीन माह पहले ही उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म हुई और अगली परीक्षा भी आ गई। एक से दूसरी परीक्षा के बीच कम से कम चार माह का वक्त दिया जाना चाहिए। जिस वक्त प्रदर्शन चल रहा था, उसी दौरान यूनिवर्सिटी ने उन सभी कॉलेजों में प्राचार्य व डायरेक्टर को फोन लगाया, जहां के छात्र यहां पहुंचे थे। फोन पर यूनिवर्सिटी की तरफ से पूछा गया कि क्या कोर्स पूरा नहीं हुआ है, क्या छात्रों को अगली परीक्षा की तैयारी नहीं करवाई गई है? करीब आधा दर्जन कॉलेजों में बात हुई। इस दौरान कॉलेजों ने कहा, सेकंड सेमेस्टर का कोर्स पूरा हो गया है, इसलिए छात्रों को परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने छात्रों की मांग मानने से इनकार कर दिया।

शेड्यूल पटरी पर लाने के लिए जल्दी परीक्षा- दरअसल, एमबीए सेकंड सेमेस्टर की यह परीक्षा अप्रैल-मई में हो जानी थी, लेकिन डेढ़ माह देरी से जून में हो रही है। शेड्यूल पटरी पर लाने के लिए यूनिवर्सिटी ने जल्दी परीक्षा का प्लान बनाया। यूनिवर्सिटी के अनुसार कॉलेजों को पहले ही कह दिया गया था कि समय पर कोर्स पूरा करवाएं।

पश्चिमी हवा ने बढ़ाई गर्मी, जून की सबसे गर्म दोपहर

39.6 डिग्री तापमान के साथ पहली बार सामान्य स्तर पर पहुंचा

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी तापमान में 1 डिग्री का इजाफा हुआ और 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इससे लोग काफी हलाकान हो गए। अभी मौसम का जो सिस्टम बना हुआ है उससे अनुमान है कि दिन का पारा 40 डिग्री पार जा सकता है। मंगलवार सुबह से भी मौसम साफ है। अभी स्थिति यह है कि सुबह 11 बजे बाद ही तेज गर्मी का असर शुरू हो जाता है जो शाम 4 बजे तक ज्यादा रहता है।॥ खास बात यह कि जून माह में पहली पार दिन का तापमान 39.6 (0) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने के साथ पहली बार सामान्य पर आया है। रात में भी गर्मी का असर है।

सोमवार रात का तापमान 26.2 (+2) डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि 12 जून से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसी दौरान 3-4 दिन में मानसून भी मप्र में दाखिल हो सकता है। यह मंडला, बालाघाट और आसपास के जिलों से प्रवेश करेगा। इंदौर में 15 जून के बाद ही इसकी

एंट्री होगी। यदि पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो मानसून के एंटर होने से पहले प्रदेश में तेज गर्मी का असर रहता है। सबसे ज्यादा ग्वालियर-चंबल गर्म रहता है, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग भी जमकर तपते हैं। जून के आखिरी दिनों में ही टेम्प्रेचर से थोड़ी राहत मिलने लगती है। हालांकि, जून में रात का टेम्प्रेचर 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क जाता है। अबकी बार भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

इसलिए तेजी से बढ़ी गर्मी

मौसम विभाग के मुताबिक पिछले एक हफ्ते के दौरान वेस्टर्न डिस्टरबेंस हिमालय के उत्तर से गुजरा। उसका देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों पर कोई खास असर नहीं हुआ। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है। साथ ही पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों का तापमान पिछले दो दिनों से 48-49 डिग्री चल रहा है। हवा की दिशा पश्चिमी है। हवा में नमी न के बराबर हो गई है। इसी का नतीजा है कि उत्तर भारत के राज्यों में गर्म हवाएं चल रही हैं। इसका असर इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में है।

नया संकट : गिट्टी-मुरम की सप्लाय बंद

खनिज नीति के नए नियमों के विरोध में शहर के 100 स्टोन क्रशर प्लांट बंद, अधिकतर प्रोजेक्ट अटके

इंदौर (एजेंसी)। प्रदेशभर में संचालित होने वाले 2000 से ज्यादा स्टोन क्रशर प्लांट 8 दिन से प्रदेश की खनिज नीति के विरोध में हड़ताल पर हैं। इंदौर के आसपास के करीब 100 प्लांट बंद पड़े हैं। इसके चलते शहर में चल रहे अधिकतर प्रोजेक्ट अटक गए हैं। इंदौर शहर में मुख्य रूप से कम्पेल और केवड़ेश्वर के आसपास 20 से ज्यादा तो बेटमा में भी 70 से अधिक खदानें हैं। सभी ठप पड़ी हैं। कहीं भी गिट्टी-मुरम या अन्य निर्माण सामग्री नहीं पहुंचाई जा रही है। इसके चलते कई प्रोजेक्ट अटक गए। प्रोजेक्ट ही नहीं, इन उत्पादों के आधार पर मिलने वाले अन्य उत्पाद जैसे सीमेंट, ईंट, टाइल, पैवर ब्लॉक, प्री कास्टिंग जैसी 500 से ज्यादा इकाइयां भी रॉ मटेरियल नहीं मिलने से बंद हैं। हाईवे और फ्लायओवर बनाने वालों का काम भी अटक गया है। जिनके पास स्टॉक था वो भी खत्म हो रहा है। सिर्फ हाईवे, फ्लायओवर ही नहीं मकान निर्माण से लेकर कॉलोनियों की गलियों में भी सड़कों के काम रुके हुए हैं। सभी प्रभावित उद्योगों के 25 हजार से ज्यादा मजदूरों की रोजी पर भी संकट है।

8 दिन से प्लांट हड़ताल पर हैं, 2 हजार प्लांट प्रदेशभर में

500 से ज्यादा इकाइयां रॉ मटेरियल नहीं मिलने से प्रभावित, रॉयल्टी, स्टाम्प ड्यूटी जैसे मुद्दे- इंदौर टाइल्स एवं सेनेटरी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने बताया क्रशर प्लांट मालिकों की कई परेशानियां हैं, जिनका निराकरण नहीं हो

रहा। सरकार रॉयल्टी नहीं ले रही है, खदानें अलॉट नहीं कर रही। जो खदानें संचालित हो रहीं, उन पर भी अधिक रॉयल्टी के अलावा स्टाम्प ड्यूटी की मार पड़ रही। जियो टैगिंग व्यवस्था में सुधार का भी मुद्दा है।

फ्लाईऐश की भी कमी

गिट्टी-मरम के अलावा थर्मल पॉवर प्लांट से मिलने वाली फ्लाईऐश भी समय पर नहीं मिल पा रही। फ्लाईऐश का इस्तेमाल मुरम के विकल्प के रूप में किया जाता है। वह भी नहीं आ रही है। इसके चलते भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

इंदौर-हरदा हाईवे प्रोजेक्ट ठप

इंदौर-हरदा रोड निर्माण का काम कर रही कंपनी पीडी अग्रवाल के पवन अग्रवाल ने बताया हमारा प्रोजेक्ट 5 दिन से रुका हुआ है। हमारा खुद का एक क्रशर प्लांट है, लेकिन हमें भी मुरम और गिट्टी की सप्लाय नहीं हो सकी। दरअसल, हमारा प्लांट ऑपरेट करने वालों ने भी संगठन का हिस्सा होने के चलते माल देने से इनकार कर दिया है।

संपादकीय

ट्रंप के कारण जल रहा अमेरिका

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना फैसलों और अगंभीरता के कारण दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, उसे गृहयुद्ध भले न कहें, लेकिन उस जैसा मानना गलत नहीं होगा। हिंसा से भी आगे अब मामला संवैधानिक टकराव का भी होता जा रहा है। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजेलिस में बीते पांच दिन से अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर हैं। वहां बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। स्थानीय पुलिस की नाकामी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां सीधे सेना (नेशनल गार्ड्स) को मैदान में उतार दिया है। इसके खिलाफ कैलिफोर्निया राज्य के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इसे राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया है। क्योंकि नेशनल गार्ड्स की नियुक्ति का फैसला उनसे पूछे बिना ही किया गया था। इसके बाद ट्रंप ने गवर्नर को हटाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। कुल मिलाकर हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप की नीति के तहत अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है। इसी के तहत अप्रवासन विभाग देशभर में छापेमारी अभियान चला रहा है। अप्रवासन विभाग ने हाल ही में लॉस एंजेलिस में भी अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान चलाया और अप्रवासन विभाग और सीमा शुल्क विभाग ने लॉस एंजेलिस के दो होम डिपो, एक डोनट शॉप और एक कपड़ों को गोदाम से कथित तौर पर अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई लॉस एंजेलिस के फैशन डिस्ट्रिक्ट इलाके में की। अप्रवासन विभाग ने शुक्रवार को 44 लोगों को हिरासत में लिया और एक हफ्ते में लॉस एंजेलिस में कुल 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और हिंसा शुरू हो गई। सर्वाधिक उग्र प्रतिक्रिया लॉस एंजेलिस शहर में हुई। अब आलम यह है कि प्रदर्शनकारी और सुरक्षाबल आमने-सामने हैं और पूरे शहर में अराजकता का माहौल है। विरोध करने वाले ज्यादातर मैक्सिकन लोग हैं, जो अमेरिका से वापस नहीं जाना चाहते। इन लोगों ने ट्रंप सरकार का विरोध किया औरसामाजिक संगठन भी हिरासत में लिए गए लोगों के समर्थन में आ गए। जिन डिटेंशन सेंटर्स में कथित अवैध अप्रवासियों को रखा गया था, उनके बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू की और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद लोग नहीं माने। हालात बिगड़ते देख राष्ट्रपति ट्रंप ने लॉस एंजेलिस में बिना कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम से पूछे, हिंसा ग्रस्त इलाकों में नेशनल गार्ड्स की तैनाती कर दी। इस पर कैलिफोर्निया गवर्नर ने नाराजगी जताई और इसे राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। न्यूसम ने नेशनल गार्ड्स की तैनाती वापस लेने की मांग की है। हालांकि ट्रंप भी अड़े हुए हैं और अब उन्होंने मरीन कमांडो की तैनाती करने का भी आदेश दे दिया है। इसी बीच पेंटागन ने लॉस एंजेलिस में हालात पर काबू पाने के लिए वहं 700 मरीन्स को तैनात करने की घोषणा की है। वास्तव में ट्रंप के दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद यह माना जा रहा था कि वो पहले की तुलना में ज्यादा जिम्मेदारी से काम करेंगे और सच में 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' को गंभीरतापूर्वक अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन हकीकत में उल्टा ही हो रहा है। लगता है कि ट्रंप अमेरिका को अपनी निजी कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं। इसका खुद अमेरिका में भी विरोध होने लगा है। आप्रवासन का मुद्दा तो शुरूआत है। अगर ट्रंप का रवैया नहीं सुधरा तो उनका पद पर बने रहना भी मुश्किल होगा।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर राजनीति की आंच से बचाव

भारत में न्यायपालिका को संविधान द्वारा स्वतंत्र और स्वायत्त घोषित किया गया है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद कोई जज राजनीतिक दल में शामिल होता है या किसी सरकारी संस्था में उच्च पद ग्रहण करता है, तो इस स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो जाते हैं। यह सवाल केवल वर्तमान के बारे में नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है, जिसमें न्यायिक पदों का राजनीतिक उपयोग होने लगे।जस्टिस गवई का यह रुख ऐसे समय में आया है जब देश में न्यायपालिका और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद से कानून पास कर इस व्यवस्था को बदल दिया और समिति से न्यायपालिका को बाहर कर दिया। इस घटनाक्रम ने फिर से न्यायपालिका की भूमिका और अधिकारों पर बहस को जन्म दे दिया।

नजरिया

अजय कुमार
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारत की न्यायपालिका में एक नई और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है, जब देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने यह ऐलान किया कि वे रिटायरमेंट के बाद किसी भी सरकारी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। इस साहसिक निर्णय ने सिर्फ न्यायपालिका की गरिमा को नया सम्मान दिया है, बल्कि जनता के मन में भरोसे की उस डोर को भी मजबूत किया है जो पिछले कुछ समय से कई घटनाओं के चलते कमजोर होती जा रही थी। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनके कुछ अन्य साथी न्यायाधीशों ने भी यह संकल्प लिया है कि वे भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पद या राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं रखेंगे।

चीफ जस्टिस गवई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से उन घटनाओं की ओर इशारा करता है, जिनमें कुछ रिटायर्ड जजों ने सरकारी पद स्वीकार किये हैं या राजनीति में सक्रिय भागीदारी ली है। मसलन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया गया और हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और सांसद बन चुके हैं।जस्टिस गवई का कहना है कि अगर कोई जज रिटायरमेंट के बाद तुरंत कोई सरकारी पद या राजनीतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता है, तो इससे जनता के बीच यह संदेश जाता है कि शायद उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान फैसले किसी स्वार्थ या लालच के तहत लिये थे। इससे न्यायपालिका की साख पर आंच आती है और निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। वे कहते हैं, न्यायपालिका को केवल न्याय करना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए कि वह पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदार है। लोगों का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।

भारत में न्यायपालिका को संविधान द्वारा स्वतंत्र और स्वायत्त घोषित किया गया है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद कोई जज राजनीतिक दल में शामिल होता है या किसी सरकारी संस्था में उच्च पद ग्रहण करता है, तो इस स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो जाते हैं। यह सवाल केवल वर्तमान के बारे में नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए भी एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत हो सकती है, जिसमें न्यायिक पदों का राजनीतिक उपयोग होने लगे। जस्टिस गवई का यह रुख ऐसे समय में आया है जब देश में न्यायपालिका और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नियुक्ति समिति में मुख्य न्यायाधीश या उनके प्रतिनिधि को शामिल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद से कानून पास कर इस व्यवस्था को बदल दिया और समिति से न्यायपालिका को बाहर कर दिया। इस घटनाक्रम ने फिर से न्यायपालिका की भूमिका और अधिकारों पर बहस को जन्म दे दिया।

सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियों की बात नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाये हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एसआईटी जांच की खबर सोशल मीडिया पर छाई रही, लेकिन वे अब भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। वहीं अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को भी एसआईटी जांच का सामना करना पड़ा और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यह दोहरे मापदंड न्यायपालिका पर उठ रहे सवालों को और हवा देते हैं।इन सबके बीच, जस्टिस गवई ने कॉलेजियम प्रणाली की भी आलोचना की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किसी भी हाल में खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, लेकिन कोई भी सुधार इस तरह नहीं होना चाहिए कि जजों की नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाए। उनका यह बयान उस चल रही बहस में एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर आया है, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली को खत्म कर न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ाने की मांग हो रही है।

आज का दौर ऐसा है जब न्यायपालिका को सिर्फ निष्पक्ष न्याय देने के अलावा खुद को निष्पक्ष दिखाने की भी जिम्मेदारी उठानी होगी। जस्टिस गवई ने यह भी सुझाव दिया कि जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि जनता को यह भरोसा हो कि जज किसी भी तरह के लालच या दबाव में नहीं हैं। यह विचार न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देता है बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है।इस पूरी चर्चा का एक पहलू यह भी है कि न्यायपालिका में लंबे समय से कुछ नाम ऐसे उभरे हैं, जिन्होंने सेवा के बाद ऐसे निर्णय लिये जो विवाद का कारण बने। रंजन गोगोई का राज्यसभा में जाना उस समय सुर्खियों में रहा जब उन्होंने राफेल, राम मंदिर और एनआरसी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए थे। इसी तरह, जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों में सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और बाद में बीजेपी से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। इन घटनाओं ने यह संदेह पैदा किया कि कहीं जजों के फैसलों के पीछे भविष्य के लाभ की योजना तो नहीं छुपी होती?

इस संदर्भ में, जस्टिस गवई का निर्णय एक मिसाल बन सकता है, अगर आने वाले समय में अन्य न्यायाधीश भी इसी परंपरा का पालन करें। यह केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और न्यायिक प्रणाली के लिए एक नयी दिशा और सोच का प्रतीक बन सकता है।लेकिन इस सब के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह के व्यक्तिगत निर्णयों से पूरे सिस्टम की खामियों को दूर किया जा सकता है? कॉलेजियम सिस्टम की अपारदर्शिता, जजों की जवाबदेही की कमी, न्यायिक नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद, और सरकार की बढ़ती दखल जैसे मुद्दों का समाधान केवल नैतिकता के भरोसे छोड़ा जा सकता है? सिस्टम में व्यापक सुधार की आवश्यकता अब पहले से कहीं ज्यादा है। संसद और न्यायपालिका के बीच विश्वास की डोर को मजबूत करने के लिए संवैधानिक मर्यादाओं और संतुलन की पुनर्स्थापना जरूरी है। न्यायपालिका को न केवल स्वतंत्र रहना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र दिखना भी चाहिए।

जस्टिस बीआर गवई का फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह न केवल न्यायपालिका की छवि सुधारने का प्रयास है, बल्कि यह जनता को यह संदेश भी देता है कि देश में अब भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने पद की गरिमा के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी खड़े हैं। उनकी यह पहल भारत की न्यायिक प्रणाली को नई दिशा दे सकती है अगर इसे एक स्थायी परंपरा में बदला जाए।न्यायपालिका पर जनता का भरोसा तभी कायम रह सकता है जब न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि होता हुआ भी दिखे। और जस्टिस गवई की तरह अगर हर न्यायाधीश यह तय कर ले कि उनका काम सिर्फ न्याय करना है, किसी पुरस्कार की उम्मीद में नहीं, तब ही भारत की न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे ईमानदार और मजबूत संस्थाओं में शुमार हो सकती है।

प्रेम, पाप और पतन, रिश्तों की टूटती मर्यादाएं

मुद्दा

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
लेखक स्तंभकार हैं।

समाज एक दर्पण की भांति होता है, जो कुछ हमारे भीतर है, वही उसकी सतह पर उभरता है। जब हम प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और समर्पण से भरे होते हैं, तो समाज भी उन्हीं मूल्यों की अभिव्यक्ति बनता है। किंतु जब भीतर भय, असंतोष, अस्वीकार और क्रूरता जन्म ले लेती है, तब वही समाज अपने ही मूल्यों को नोचने लगता है। हाल ही में सामने आए राजा हत्याकांड और पूर्व में चर्चित सौरभ ड्रम हत्याकांड जैसे मामले समाज के इसी क्षरणशील चेहरे को उजागर करते हैं, जिसमें अब ममता की मूरत कही जाने वाली नारी भी अपराध की भयंकर छाया में नजर आने लगी है। यह केवल स्त्री के अपराध की कथा नहीं है बल्कि यह उस सामाजिक ढांचे की विफलता की भी कहानी है जिसने संबंधों को जकड़न में बदल दिया है और स्वतंत्रता की व्याख्या को स्वेच्छाचार तक सीमित कर दिया है।

एक समय था, जब नारी शब्द अपने आप में करुणा, सहनशीलता और ममता का पर्याय माना जाता था। वह सृजन की शक्ति थी, जीवन की जननी थी और समाज की आत्मा मानी जाती थी। परंतु आज, बदलते समय और परिवेश में जब हम समाचार पत्रों की सुर्खियों में कुछ स्त्रियों के द्वारा किए गए नृशंस अपराधों को देखते हैं, तो मन स्तब्ध रह जाता है। राजा हत्याकांड में एक युवती, जो हाल ही में विवाह के बंधन में बंधी थी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाती है। घटनाक्रम बताता है कि पहले शादी, फिर हनीमून के नाम पर एक योजनाबद्ध हत्या, यह कहानी किसी अपराध कथा से कम नहीं लगती। परंतु यह कल्पना नहीं, कटु यथार्थ है। ऐसा ही कुछ सौरभ हत्याकांड में भी देखा गया, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर, उसे एक ड्रम में भरकर छिपा दिया। ये घटनाएं केवल कानून के उल्लंघन की नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं और विश्वास की निर्मम हत्या हैं।

नारी की भूमिका सदियों से सहनशीलता और बलिदान की रही है। किंतु आज जब स्त्रियाँ स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ रही हैं, तब यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व और विवेक का भी परिचय दें। परंतु कुछ घटनाओं में देखा गया है कि व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपराध का रास्ता अपनाना अब कुछ स्त्रियों के लिए सामान्य विकल्प बनता जा रहा है। यह प्रवृत्ति केवल कानून के उल्लंघन की नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवीय मूल्यों के पतन की सूचक है। यह भी स्मरणीय है कि पुरुषों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या आज भी अधिक है, परंतु जब एक स्त्री, जिसे समाज ने करुणा की प्रतिमा माना है, जब वह निर्ममता का मार्ग चुनती है, तो उसकी गूंज अधिक तीव्र होती है। शायद इसी कारण महिलाओं द्वारा किए गए अपराधों की खबरें समाज में गहरी बेचैनी उत्पन्न करती हैं।

एक दौर था जब नारी पर हो रहे अत्याचार जैसे कि दहेज हत्या, बलात्कार, यौन शोषण, घरेलू हिंसा, समाचार पत्रों के कालिख भरे पन्नों पर रोजाना छपते थे। आज भी वे अपराध समाप्त नहीं हुए हैं, किंतु समाज की संवेदनशीलता धीरे-धीरे उन घटनाओं के प्रति शिथिल होती जा रही है, शायद इसलिए कि समाज ने नारी को 'सहनशीलता' का पाठ सदियों से पढ़ाया है। मगर जब उसी स्त्री से कोई हिंसा, छल, हत्या या षड्यंत्र जुड़ जाए, तब पूरी सामाजिक चेतना चौंक उठती है। यह विस्मय केवल इसलिए होता है क्योंकि नारी से समाज ने कभी करूरता की अपेक्षा नहीं की थी। उसे तो सृष्टि की जननी, ममता की साकार प्रतिमा माना गया है और जब वही स्त्री किसी की जीवनलीला समाप्त कर दे, तो यह न केवल कानूनी अपराध होता है, बल्कि हमारी सामूहिक नैतिकता पर एक गहरा प्रहार भी होता है।

इन घटनाओं को केवल अपराध के रूप में देखना उन्हें अधूरा समझना होगा। इसके पीछे एक जटिल सामाजिक और मानसिक तंत्र है। आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा प्रेम को 'स्वेच्छाचार', अंतरजातीय विवाह को 'अपमान' और स्त्री की स्वतंत्रता को 'उच्छृंखलता' मानता है। ऐसे में जब कोई लड़की अपने प्रेम को स्वीकारना चाहती है, तो उसके आगे पारिवारिक, सामाजिक और जातीय पहरे खड़े कर दिए जाते हैं। यह विडंबना है कि 21वीं सदी के तथाकथित प्रगतिशील युग में भी प्रेम को वर्जना, विवाह को अनिवार्यता और स्त्री को त्याग की मूर्ति मानने वाली मानसिकता समाज में जीवित है।

राजा हत्याकांड जैसी घटनाएं इसी कुंठित सामाजिक सोच की कोख से जन्म लेती हैं। जब प्रेम को अपराध मान लिया जाए और विवाह को सामाजिक प्रतिष्ठा का बंधन बना दिया जाए, तो कई बार युवा ऐसी विकृत राहों की ओर मुड़ जाते हैं, जहां संबंधों की गरिमा, जीवन की महत्ता और मानवता की मूल भावना सभी कुचल दी जाती हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या समाज की स्वीकृति के अभाव में हत्या या छल को स्वीकार्य ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रेम की स्वीकृति न मिले, तो विरोध का मार्ग लोकतांत्रिक होना चाहिए, हिंसक नहीं।

इस घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मनोविज्ञान की भी है। जब एक युवती को उसकी भावनाओं के विरुद्ध विवाह के

बंधन में बांध दिया जाता है, तो उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू होता है। वह बंधन जिसे समाज 'पवित्र गठबंधन' कहता है, उस स्त्री के लिए बोझ बन जाता है। एक स्त्री जब स्वयं को जीवन के एक ऐसे बंद कमरे में पाती है जहाँ उसकी इच्छा, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का दम घुटता है, तब कभी-कभी वह आक्रोश की ज्वाला में जलने लगती है। यह आक्रोश भीतर ही भीतर उसे इतना खोखला कर देता है कि वह निर्णय की क्षमता खो बैठती है और घातक कदम उठा लेती है। धीरे-धीरे वह उस बंधन को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से करूर निर्णय लेने लगती है। कई बार यह निर्णय केवल तलाक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हत्या जैसे जघन्य कृत्य का रूप ले लेता है। यह मानसिक संतुलन की विकृति है, जो सामाजिक जकड़नों, प्रेम की अस्वीकृति और भावनात्मक संवाद की अनुपस्थिति से जन्म लेती है। यह मानसिक संतुलन का संकट न केवल स्त्रियों में, बल्कि समाज के हर वर्ग में तीव्र होता जा रहा है।

आज आवश्यकता है कि हम केवल स्त्री या पुरुष के अपराध को देखकर आक्रोशित न हों, बल्कि उस पूरे सामाजिक परिवेश की जांच करें जिसने इन अपराधों को जन्म दिया है। विवाह अब भी हमारे समाज में दो आत्माओं का नहीं, दो परिवारों का समझौता माना जाता है। प्रेम अभी भी वर्जित है, विशेषकर तब जब वह जाति, धर्म या सामाजिक मर्यादाओं की सीमाओं से परे हो। ऐसे में जब कोई स्त्री या पुरुष इन सीमाओं को लांघता है, तो समाज उन्हें दुत्कारता है, परिवार उन्हें त्याग देता है और तब वे असहाय होकर ऐसे निर्णय लेते हैं जो पूरे समाज को हिला देते हैं।

इस विकृति का समाधान केवल कठोर कानूनों में नहीं है। कानून दंड दे सकता है, परंतु चेतना नहीं जगा सकता। समाधान है शिक्षा, संवाद, और संवेदना में। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना होगा कि प्रेम एक अधिकार है, परंतु उससे जुड़ा उत्तरदायित्व भी उतना ही गंभीर है। यदि कोई संबंध असफल हो जाए, तो उसे समाप्त करने का संवैधानिक मार्ग तलाक है, हत्या या छल से समस्या नहीं सुलझती, बल्कि अनेक जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। समाज को भी अब आत्मपरीक्षण की आवश्यकता है। केवल स्त्रियों या पुरुषों को दोष देने से बात नहीं बनेगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रेम, विवाह और स्वतंत्रता के निर्णय व्यक्तिगत होते हैं, जिनमें परिवार को मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए, न कि निर्णायक की। माता-पिता को भी अब यह समझना होगा कि उनके बच्चों की भावनाएं, उनकी पसंद-नापसंद भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि समाज का तथाकथित सम्मान। जब पारिवारिक संवाद खुला होगा, तभी छिपे हुए प्रेम और झूठी शादी जैसी त्रासदियां रोकी जा सकेंगी।

विद्यालयों और महाविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य और संबंधों की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। युवाओं को यह सिखाया जाना चाहिए कि असहमति, असफलता और ठुकराए जाने की पीड़ा को भी गरिमा के साथ स्वीकारना जीवन का हिस्सा है। वहीं माता-पिता को भी अब यह समझना होगा कि अपने बच्चों की भावनाओं को सम्मान देना आवश्यक है। जब संवाद के दरवाजे खुले होंगे, तभी अपराध के पीछे छिपे द्वार बंद होंगे।

स्त्री की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह हर सीमा को तोड़े और पुरुष की सत्ता का यह अर्थ नहीं है कि वह स्त्री की इच्छाओं को कुचले। जब तक यह संतुलन नहीं बनता, तब तक समाज हिंसक टकरावों का अखाड़ा बना रहेगा। राजा हत्याकांड हो या सौरभ ड्रम हत्याकांड- इन घटनाओं को केवल 'क्राइम न्यूज' बनाकर छोड़ देना हमारी सामूहिक संवेदना की हत्या होगी। इन घटनाओं को आत्मपरीक्षण का अवसर बनाना होगा, एक ऐसा अवसर, जहां हम स्त्री-पुरुष संबंधों, सामाजिक स्वीकृति, प्रेम की परिभाषा और विवाह की व्याख्या को पुनः परखें।

आज समाज को यह समझना होगा कि स्त्री अब केवल श्रद्धा की पात्र नहीं है, वह आलोचना की पात्र भी हो सकती है और यह आलोचना तभी सार्थक होगी जब वह पुरुष के साथ न्याय करते हुए स्त्री के लिए भी उत्तरदायित्व निर्धारित करे। समानता का अर्थ है- समान अधिकार और समान उत्तरदायित्व। यदि एक स्त्री स्वतंत्र है, तो वह उत्तरदायी भी है। अपराध, चाहे स्त्री करे या पुरुष, उसका दंड समान होना चाहिए और समाज की प्रतिक्रिया भी समान होनी चाहिए।

यह समय हमारे समाज की आत्मा के लिए एक अग्निपरीक्षा का है। हमें यह तय करना है कि हम अपने सामाजिक ढांचे को संवाद, सहमति और संवेदना की नींव पर पुनर्निर्मित करेंगे या फिर हम उन समाचारों के आदि हो जाएंगे जिनमें प्रेम, विवाह और नारीत्व की हत्या होती रहेगी। यदि हमने समय रहते चेतना नहीं दिखाई, तो वह दिन दूर नहीं जब ममता की मूरत से रक्त टपकता हुआ दिखेगा, और समाज उस दृश्य को केवल एक और 'ब्रेकिंग न्यूज़' मानकर आगे बढ़ जाएगा।

आज का समाज एक अजीब दोराहे पर खड़ा है। जहां एक ओर महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वहीं कुछ घटनाएं उनके उस रूप को भी सामने ला रही हैं जो ममता की मूरत से अलग, कठोर और निर्मम है। परंतु यह सम्पूर्ण स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करती और न ही यह संकेत है कि स्त्रियाँ अपराध की ओर प्रवृत्त हो रही हैं। यह महज उन कुछ असामाजिक विकृतियों की कथा है जिन्हें प्रेम, स्वतंत्रता और अस्वीकृति की त्रासदी ने जन्म दिया है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज के दो पहिए हैं। यदि एक पर आक्षेप हो, तो दूसरे को भी आत्मपरीक्षण करना होगा। यह समय है कि हम अपने समाज को न्याय, करुणा और संवाद के मूल्यों पर पुनः गढ़ें, ताकि कोई राजा, कोई सौरभ फिर कभी प्रेम के नाम पर हत्याओं की भेंट न चढ़े। यह समय है जब समाज को यह स्वीकार करना होगा कि प्रेम का मार्ग स्वतंत्रता से होकर जाता है, न कि बंदूक की नली से। ममता की मूरत जब हाथ में खंजर ले ले, तो यह न केवल नारीत्व का अपमान है, बल्कि सम्पूर्ण सभ्यता का अपमान है।

संविधान में चौथा खम्भा कहां है?

दृष्टिकोण

ध्रुव शुक्ल
लेखक साहित्यकार हैं।

हम बीते एक दशक से मीडिया चैनलों पर केवल यही दृश्य देख रहे हैं कि जैसे पूरे देश के लोगों को राजनीतिक दलों की हार-जीत में ही अपना समय गँवाना है। जैसे हमारे पास और कोई काम न हो। हमें तो बस राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की एक-दूसरे पर झल्लाहट देखना है और उनकी घृणा से भरी गालियाँ सुनना है। हमें सारे काम छोड़कर मीडिया चैनलों पर हल्ला बोल और दंगल देखना है। एंकरों की चीखों और कुतर्कों से भरी झूठी खबरें अपने दिमाग में ठूँसकर अवसाद से भर जाना है। क्या हमारा जन्म सत्ता के प्रतियोगियों को अपनी स्वाधीनता सौंपकर उनकी छलपूर्ण होड़ देखने के लिए हुआ है?

हम मीडिया के मंच पर ऐसा कोई सम्वाद नहीं सुन रहे जिसमें इस बात की गहन चिन्ता हो कि देश की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली और समृद्धि की राहें कैसी होना चाहिए। उनमें कौन-सी कमियाँ आ गयी हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। यह तब ही सम्भव है जब मीडिया अपनी इकतरफ़ा ढिंढोरची की भूमिका को त्यागकर देश के जनजीवन का पक्षधर बनने पर विचार करे। मीडिया हमारी ही चुनी हुई सरकार से चमचमाते विज्ञापन लेकर अकूत धन कमा रहा है और हमें देश की धूल-धूसरित हकीकत नहीं दिखा रहा है। वह घटनाओं का ग़लत नामकरण करके हमें भ्रमित कर रहा है।

हम तो यही समझते रहे कि मीडिया का काम घटनाओं को यथातथ्य उजागर करते हुए इस तरह दिखाना है कि लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर अपने संवैधानिक अधिकारों को पहचानें और परस्पर न्यायपूर्ण व्यवहार के प्रति उत्सुक हों। पर मीडिया तो रोज़ अपने कुटिल युद्धक्षेत्र में नये चक्रव्यूह रचकर हमें फाँसता है, डराकर अकेला करता है। अनीति, अश्लीलता और अराजकता का महिमामण्डन करता है। मीडिया में अभद्रता मूल्य की तरह स्थापित होकर उसे एण्टी सोशल मीडिया के रूप में बदल रही है।

विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के तीन खम्भों पर राज्य व्यवस्था को जनता के पक्ष में मजबूती से खड़ी रहने का उपाय संविधान में किया गया है जो समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के उद्देश्य को देश के जीवन में चरितार्थ करने के लिए है। संविधान में चौथे खम्भे की कोई परिकल्पना नहीं है। मीडिया की प्रतिष्ठा तो संविधान में दी गयी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। सच्चे अर्थों में तो मीडिया को जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गयी सरकार का ऐसा स्थायी प्रतिपक्ष होना चाहिए जो केवल चुनी हुई सरकार की ही नहीं, उसे चुनने वाली जनता की भी खुली आलोचना कर सके।

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सहज कवि, निर्भीक संत व समाज सुधारक थे कबीर

कबीर अपनी बेबाक रचनाधर्मिता से सभी समुदायों में काफी लोकप्रिय हुए, तो दूसरी ओर धर्म की दुकान चलाने वाले ढोंगी और कट्टरपंथियों के आँखों की किरकिरी भी बन गये। विभिन्न साजिशों के तहत 52 बार उनकी हत्या का असफल प्रयास भी किया गया।

कबीर जयंती पर विशेष

विनोद कुमार विक्की

15वीं शताब्दी में वाराणसी में जन्म लेने वाले कबीर एक महान भारतीय कवि, संत और समाज सुधारक थे। कबीर सागर के अनुसार सन 1398 (संवत 1455), में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मूहर्त के समय लहरतारा तालाब में कमल पर इनका अवतरण हुआ था। जहां से उठा कर नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनकी परवरिश की। सरल और सहज व्यक्तित्व वाले कबीर सत्यनिष्ठ एवं निडर थे। ऐसा माना जाता है कि वो पढ़े-लिखे नहीं थे, उनके दोहों को उनके दो शिष्यों भागो दास और धर्मदास द्वारा ही लिखा या संग्रीहित किया गया था। उनकी रचनाएं और शिक्षाएं बताती हैं कि वे एक ज्ञानी और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। कबीर बीजक, कबीर साखी,कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, ग्रंथावली आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में सधुक्कड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी भाषा के तहत राजस्थानी, पंजाबी , हरियाणवी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता देखने को मिलती हैं। इनकी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद कर विश्व पटल पर लाने में रवींद्रनाथ ठाकुर की अहम् भूमिका है। कबीर की रचनावली को समृद्ध करने में बाबू श्याम सुन्दर दास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी सहित अनेक हिन्दी विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कबीर और उनकी साहित्यिक साधना पर कई ग्रन्थ लिखे हैं। कबीर के 226 दोहे को सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रन्थ साहिब में भी शामिल किया गया है।

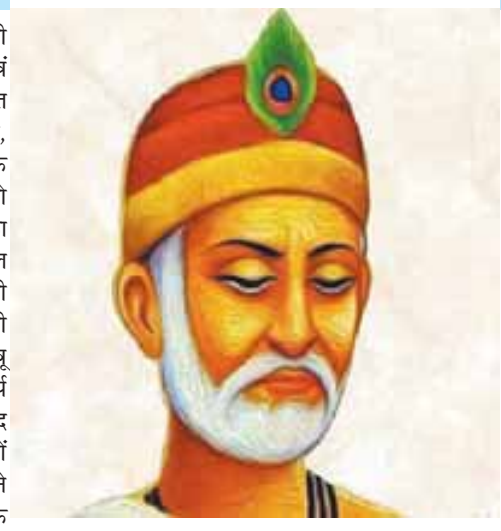

उनकी शिक्षाएं एकता और समानता, आध्यात्मिकता,नैतिकता और सदाचार तथा जाति और धर्म की विसंगति पर केंद्रित था। कबीर की सरल और सहज कविताएं भक्ति और आध्यात्मिकता से भरपूर हैं और आज भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं,जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कबीर एक महान व्यंग्यकार भी थे। सरल भाषा वाली उनकी व्यंग्य रचनाओं में तीखापन और सटीकता है, जो समाज को आईना दिखाने का काम करती है। एकेश्वरवाद के प्रवर्तक कबीर सामाजिक कुरीति, कर्मकांड, अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा , पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होने भारतीय समाज में जातिगत और धार्मिक विसंगतियों पर जमकर कटाक्ष किया । हाथों में इकतारा लेकर अपनी व्यंग्यात्मक रचना शैली से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया।

जाति और धर्म की रूढ़ियों पर लिखित

'हिन्दू कहें मोहि राम पियारा, तुरक कहें रहमाना। आपस में दोऊ लड़ी-लड़ी मरैं, मरम न कोउ जाना।'

तथा

'पाहन पूजे हरि मिलैं, तो मैं पूजूं पहार।
ताते ये चाकी भली, पीसी खाय संसार।।'

तथा पाखंड और दिखावे पर व्यंग्यात्मक शैली में लिखी कांकर पाथर जोरि के मस्जिद लई बनाय।

ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय॥ आज भी प्रासंगिक हैं।

कबीर अपनी बेबाक रचनाधर्मिता से सभी समुदायों में काफी लोकप्रिय हुए, तो दूसरी ओर धर्म की दुकान चलाने वाले ढोंगी और कट्टरपंथियों के आँखों की किरकिरी भी बन गये। विभिन्न साजिशों के तहत 52 बार उनकी हत्या का असफल प्रयास भी किया गया।

हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 1575 में माघ शुक्ल एकादशी (जनवरी 1518) में यूपी के मगहर में अपने शरीर का त्याग किया।

शरीर त्याग के लिए काशी छोड़ कर मगहर चुनने के पीछे भी कबीर का तार्किक उद्देश्य था। दरअसल वो इस मिथक को दूर करना चाहते थे कि काशी में मृत्यु से मोक्ष और अपवित्र स्थल मगहर में मृत्यु से नरक की प्राप्ति होती है। एक प्रबुद्ध आत्मा के रूप में धार्मिक बंधनों से मुक्त कबीर साहेब के तत्वज्ञान पर आधारित कबीर पंथ एक आध्यात्मिक सत भक्ति मार्ग है। जिसके अनुयायी किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि से हो सकते हैं।

सत्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन

कबीर जयंती पर विशेष

डॉ. परविंदर शर्मा

लेखक सहायक प्रोफेसर हैं।

कबीर दास जी एक ऐसे संत रूपी भक्त, समाज सुधारक और उसे प्रभु की बंदगी में लीन रहने वाले एक उच्च कोटि के परमात्मा के अंश थे। जिनके जैसा ना कोई समाज में हुआ है और ना ही शायद ऐसा भक्ति में लीन रहने वाला होगा। उन्होंने सत्य के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन तथा कल्याण किया जिस समय राष्ट्र एवं देश को महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। जिससे मानव कुसंगति, छल कपट, निंदा, अहंकार, जाति भेदभाव, धार्मिक पाखंड छुड़ाकर एक सच्चा मानव बल उस समय देश में रहने वाले हर नागरिक को मंत्र दिया। उन्होंने समाज के अंदर चल रहे अंधविश्वास हो रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया। कबीर शांति भाई जीवन बताते थे और वह अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी शिक्षा दिया। उनका स्वभाव क्रांतिकारी प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने उच्च नीच तथा समाज में जाति-पाति के भेदभाव का विरोध किया। उनकी वाणी ने न केवल भक्तिकाव्य की धारा को प्रभावित किया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध भी प्रस्तुत किया। कबीर का जीवन और काव्य आज भी समाज सुधारक के रूप में उनकी पहचान को प्रगाढ़ करता है।

कबीर का जन्म 1440 के आसपास वाराणसी के निकट लहरतारा गांव में हुआ था। उनके माता-पिता के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वे जुलाहा जाति से थे। उनका जीवन प्रारंभ से ही सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना करते हुए व्यतीत हुआ। इस अनुभव ने उन्हें समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। कबीर ने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव को नकारा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईश्वर के प्रति भक्ति से ही व्यक्ति का मूल्य है, न कि जन्म से। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस विचार को व्यक्त करती हैं।

जाति-पाति पूछे नहिं कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई

कबीर जी ने धार्मिक कर्मकांडों, पूजा-पाठ और बाहरी आडंबरों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति हृदय की शुद्धता और ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम में है, न कि बाहरी क्रियाओं में। उनकी रचनाओं में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से है।

पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहार।
याते चाकी भली जो पीस खाय संसार।

कबीर जी ने समाज में समानता की वकालत की। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना और किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी रचनाओं में यह संदेश मिलता है कि सभी लोग समान हैं और उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके इलावा कबीर जी ने नारी के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने नारी को समाज में समान स्थान देने की बात की और उनके प्रति भेदभाव और अत्याचार की आलोचना की। उनकी रचनाओं में नारी के सम्मान और अधिकारों की रक्षा का संदेश स्पष्ट रूप से मिलता है। कबीर जी की प्रमुख रचनाएँ उनके दोहे, साखियाँ और रमैनी हैं। इन रचनाओं में उन्होंने जीवन, समाज, धर्म और भक्ति के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी रचनाएँ सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हैं, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। कबीर जी की वाणी ने न केवल भक्तिकाव्य की धारा को प्रभावित किया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ एक सशक्त प्रतिरोध भी प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवाधिकार की बातें की गई हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

कबीर जी एक महान संत कवि एवं समाज सुधारक थे। कबीर जी वहां सुधार लाना चाहते थे जहां पर उनको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई समाज के अंदर गिरावट है। कबीर जी ने अपनी लोकल भाषा में अपनी वाणी को लेकर समाज में फैली कृतियों तथा कुविचारों का जोर-जोर से खंडन किया। कबीर जीवन को एक ही तरीके समानता के आधार पर देखे थे। वह राम रहीम के नाम पर चल रहे भेदभाव तथा उनके बीच कुरीतियों को भरने का प्रायस किया। कबीर समाज सुधारक के साथ-साथ क्रांतिकारी योद्धा भी थे। जिन्होंने निडर भावना से समाज में चल रहे कुरीतियां पर अपने विचारों को स्पष्ट किया। विजय समाज तथा धर्म के नाम पर अंधविश्वास एवं अहिंसा व पशु बलि, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। कबीर जी ने मानव को परीक्षण ज्ञान व कर्म को ही महान बताया है। वह अपने युग के महान दार्शनिक थे। उनके लिखे दोहे आज के आधुनिक युग में प्रासंगिक है। संत कबीर का संपूर्ण साहित्य समाज को एक सही पथ दिखाकर उसे पर चलने के लिए प्रेरणा देता है।

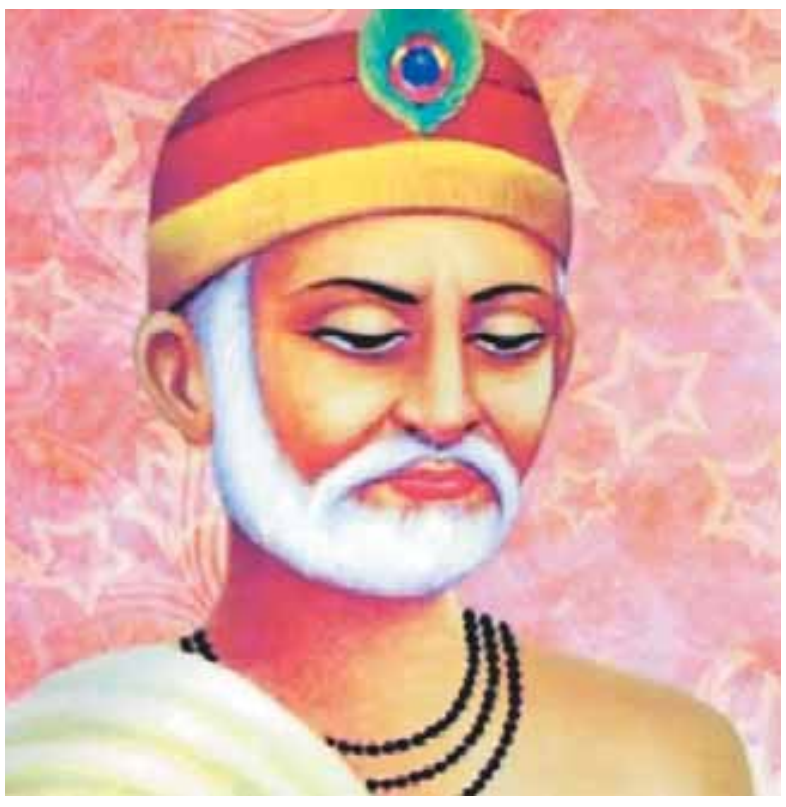

दृष्टिकोण

डॉ. तेजी ईशा

लेखक एसजीटी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग में कार्यरत हैं।

नैतिकता बोझिल होती है लेकिन इसका बोझ भी जरूरी

आज देश की करोड़ों लड़कियाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। कुछ मन के हिसाब से काम कर रही हैं, अच्छे माहौल में काम कर रही हैं। ज़्यादातर ज़रूरत के लिए ख़राब से ख़राब माहौल और बॉस के साथ काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में उनकी दोहरी ज़िम्मेदारी बनती है। उन्हें काम भी करना है और अपने लिए नैतिकता की एक रेखा भी अपने मन में खुद ही खींचनी है। आप अपने मन से अपने किसी को भी अपना साथी चुन सकती हैं। उसके साथ रहने का फ़ैसला कर सकती हैं, करना भी चाहिए। प्रेम विवाह मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए उत्तम चीज़ है। बशर्ते, आप अपने प्रेमी को पहचाने और एक सही व्यक्ति को चुनें।

एक शाम की बात है। मैं मेट्रो से घर लौट रही थी। हमेशा की तरह गर्दन झुकाए, एक किताब के पन्नों में खोए। खोए। तभी मेरे बग़ल की एक सीट ख़ाली हुई और एक लड़की के कदम उस तरफ़ बढ़ते हुए मुझे दिखे। लेकिन मेरी सीट पर बैठा एक आदमी। लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। लड़की की जाँघों पर मेरी नज़र गई। उसकी जाँघ के पास उस व्यक्ति की उँगलियाँ थीं और दोनों के बातचीत से मैं असहज हो गई। और ये भी समझ गई कि दोनों एक ही दफ़्तर में काम करते हैं। आदमी उसका बॉस है और लड़की उसके अंदर काम करती है। इतने में मेरा स्टेशन आ गया और मैं भाग के गेट पर आ गई। वहाँ आने के बाद मैंने पहली दफ़ा उस आदमी और लड़की को देखा। लड़की की उम्र 25-30 की रही होगी तो आदमी यही कोई 45-50 का होगा। मेट्रो का गेट खुला और मैं वहाँ से बाहर निकल आई। लेकिन वो घटना मेरे अंदर से नहीं निकली। मोबाइल में आए दिन कोई ना कोई रील दिल्ली मेट्रो का दिखता रहता है। कुछ हंसने लायक़ होते हैं तो कुछ को देख के गम्भीर विमर्श करने का मन करता है। लेकिन ज़िंदगी की अपनी भागम-भाग में ये सब पीछे छूट जाता है।

आज देश की करोड़ों लड़कियाँ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। कुछ मन के हिसाब से काम कर रही हैं, अच्छे माहौल में काम कर रही हैं। ज़्यादातर ज़रूरत के लिए ख़राब से ख़राब माहौल और बॉस के साथ काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में उनकी दोहरी ज़िम्मेदारी बनती है। उन्हें काम भी करना है और अपने लिए नैतिकता की एक रेखा भी अपने मन में खुद ही खींचनी है। आप अपने मन से अपने किसी को भी अपना साथी चुन सकती हैं। उसके साथ रहने का फ़ैसला कर सकती हैं, करना भी चाहिए। प्रेम विवाह मेरे ख़्याल से लड़कियों के लिए उत्तम चीज़ है। बशर्ते, आप अपने प्रेमी को पहचाने और एक सही व्यक्ति को चुनें। लेकिन अगर आप ऐसे किसी दफ़्तर में हैं जहां आपका बॉस, आपका कोई सीनियर आपको तरक़्क़ी के बदले, कम काम के बदले या कुछ प्रतिशत ज़्यादा इंक्रिमेंट के बदले आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है और वो कर रही हैं। तो आप एक ऐसी दलदल में फँस रही हैं जहां से निकलना शायद आपके लिए आसान नहीं होगा। हो सकता है कि इस दलदल में फँसते हुए आपकी जान चली जाए। या आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आप जीते-जी एक लाश में तब्दील हो जाएँ।

आप अपनी ज़रूरतों को सीमित रखिए। जितना कमा रही हैं, खर्च को उसी के हिसाब से बांधिए। शहरी चमक-धमक में आकर 'चादर से ज़्यादा पैर मत फैलाइए' ऐसा करने के बाद कोई ना कोई, कभी ना कभी आपका फ़ायदा उठाना ही चहएगा। दूसरी बात, कई बार लड़कियाँ भी शॉर्टकट अपनाना चाहती हैं। जल्दी से जल्दी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हैं। अच्छे होटल में जाना चाहती हैं। या वो सब करना चाहती हैं जो बाज़ार उन्हें चौबीसों घंटे दिखाता रहता है। ये सारी चीजें मेहनत से भी मिल सकती हैं। मिलती ही हैं और जब अपनी मेहनत से मलती है तो ये सब सिर्फ़ आपका होता है। किसी और कोई दाबा इस पर नहीं होता। ना ही इस सब के बदले आपको किसी को कुछ देना होता है। ना ही आपको अपने के विपरीत जाकर कुछ करना होता है। इसलिए आप मेहनत से मत भागिए। जितना कर सकती हैं उतना कीजिए। सपने वही है जो आपकी मेहनत से पूरे हों। किसी और से चाहे जो मिल जाए वो या तो भीख कहलाएगा या सौदेबाज़ी!

तो लड़कियों, आप ऐसे बॉस या कुलिग से सचेत रहो जो आपको सिर्फ़ 'मज़े की चीज़' समझते हैं। वो आपको अगर कुछ दे रहे हैं जो आपका अधिकार नहीं है या जो आप डिज़र्ब नहीं करते तो उसे वहीं के वहीं मना कर दो। क्योंकि वो थोड़ा देकर आपसे बहुत कुछ की उम्मीद पाले बैठे हैं। और अगर आप ये सब जानते हुए। समझते हुए उनके ट्रैप में आ ही गई हो तो अब जल्दी से जल्दी यहाँ इस ट्रैप से निकलने की सोचो क्योंकि ये आपको मानसिक तौर से खोखला कर देगा। इतना ही नहीं, हो सकता है कि आप किसी दिन इस वजह से किसी बड़ी मुश्किल में फँस जाओ। आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद आपकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाए। आप अकेले हो जो। वैसे तो अब महात्मा गांधी की बात करना ओल्ड फ़ैशन है फिर भी जाते-जाते उनका दिया एक मंत्र आपको दिए जा रही हूँ। इसे गाँठ बांध दिया तो कोई मर्द तुम्हें ठग नहीं सकेगा। गांधी बाबा कहते हैं-अगर कोई आपको आपकी क्षमता से ज़्यादा कुछ भी दे रहा है तो समझो वो आपको गुलाम बना रहा है।

उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस जंतर की मदद से आज़ाद रहोगी। किसी की गुलाम नहीं बनोगी और किसी मेट्रो में कोई सबके सामने आपकी जाँघों पे हांथ फेरने की हिम्मत नहीं करेगा।

सिंगापुर में 'लिटिल इंडिया' नाम से बसा छोटा 'भारत'

पर्यटन

डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

प्रवासियों ने अपने हिस्से का थोड़ा-थोड़ा हिंदुस्तान जोड़कर सिंगापुर में भी है एक छोटा सा 'भारत' बसाया हुआ है। 'लिटिल इंडिया' कहते हैं उसे, जो वहां बसे भारतीय मूल के लोगों और सनातनी पर्यटकों के लिए सदैव खास स्थान रहा है। 'लिटिल इंडिया' को लेकर एक किताब लिखी गई है जिसे पढ़कर दुनिया के लोग और ज्यादा जान पाएंगे। उस स्थान को लेकर किताब में न सिर्फ दोनों देशों की साक्षा संस्कृति बल्कि उसमें सामाजिक परिवर्तन, प्रारंभिक जीवन, परिसर में आयोजित होने वाले तीज-त्योहारों, आकर्षण के विभिन्न केंद्र, महत्वपूर्ण जगहें और प्राचीन काल में व्यापार करने दौरान उत्पन्न हुई चुनौतियों के संबंध में विस्तार से विवरण किया है। 1970 से पहले इस जगह को 'सेरंगून रोड' कहते थे।

किताब का नमा 'लिटिल इंडिया एंड द सिंगापुर इंडियन कम्युनिटीः थ्रू द एजेस' है जिसका बीते दिनों भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अम्बुले और सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो द्वारा संयुक्त रूप से विमोचन किया गया। सिंगापुर में भारतीयों की आबादी इस समय करीब 6 लाख 50 हजार के आसपास है, जो वहां की कुल आबादी का 10 फीसदी हिस्सा है। ये आबादी तीसरी सबसे बड़ी जातीय समूह में भी शुमार है। किताब सन्-1822 में 'लिटिल इंडिया' परिसर के मुख्य मार्ग सेरंगून रोड की स्थापना से लेकर अभी तक के कार्य कलापों का विवरण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार वहां भारतीयों ने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक विधा में खुद को चुनौतियों का सामना करके स्थापित किया था।

'लिटिल इंडिया' को लेकर 187 पन्नों की लिखी पुस्तक की लेखिका का नाम 'सौंदरा नायकी वैरावन' है, जो विश्व प्रसिद्ध राइटर हैं। उन्होंने इससे पहले भी भारतीयों पर आधा दर्जन से अधिक किताबें लिखी हैं। किताब के प्रत्येक पन्नों में उन पहलुओं का वर्णन किया गया है कि कैसे 'लिटिल इंडिया' का सिंगापुर में निर्माण हुआ और किसने उस जगह की नींव रखी थी। इसलिए कह सकते हैं कि ये पुस्तक भारतीय समुदाय के लोगों की गतिविधियों का दस्तावेज है। शुरुआती दिनों में 'लिटिल इंडिया को बसाने में सिर्फ भारतीयों ने ही बिना स्थानीय सहयोग से अपनी भूमिकाएं निभाई। पर, उसके बाद वहां की हुकूमत ने बजट आवंटन में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। चुनावों में प्रत्येक सियासी दल भारतीय मूल के वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सियासी दल बकायदा अपने घोषणा पत्रों में 'लिटिल इंडिया' को और विस्तार देने का वादा करते हैं।

ये स्थान इतना फेमस है कि सिंगापुर पहुंचने वाले तकरीबन भारतीय 'लिटिल इंडिया' जाना नहीं भूलते। उसका परिसर, रेस्तरां, खानपान और बनावट में भारतीय संस्कृति की खुशबू आती है। भवन में कार्यरत अधिकांश भारतीय ही हैं। इसमें जो होटल हैं जिनमें प्रत्येक भारतीय व्यंजन मिलते हैं। कहा जाता है कि तमिलनाडु निवासी नारायण पिल्लई सिंगापुर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। सन 1824 में सिंगापुर में मात्र 756 भारतीय रहते थे, लेकिन उसके बाद भारतीयों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ। सभी जानते हैं कि सिंगापुर एक समृद्ध और विविधता से लबरेज देश है, जो दुनिया के देशों का गहरा प्रतिबिंब है। गहरे संबंधों की मजबूत और खूबसूरत गांठें ऐसी बंधी हुई हैं जो भारत-सिंगापुर को एक सूत में सदियों से बांधी हुई हैं। लिटिल इंडिया का क्षेत्रफल करीब 45 एकड़ में है जिसके भीतर मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद व गिरिजाघर भी हैं। देशी मसालों से बनी तरकारियों के जायकों की खुशबू भी फैली होती है।

करोड़ों के सौंदर्यीकरण योजनाओं का आज होगा भूमिपूजन

514.34 लाख की लागत से होगा शिवाजी, कारगिल व अंबेडकर चौक का सौंदर्यीकरण

बैतूल। मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत विभिन्न चौराहों के सौंदर्यीकरण एवं पार्किंग निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कार्यक्रम आज बुधवार 11 जून को आयोजित किया जाएगा। इस योजना की कुल लागत 514.34 लाख रुपये है, जिसके लिए विधायक हेमंत खंडेलवाल के निरंतर प्रयासों और शासन स्तर पर की गई पैरवी के परिणामस्वरूप यह स्वीकृति प्राप्त हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के केन्द्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल करेंगे, जिन्होंने इस योजना को मूर्त रूप दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका परिषद बैतूल की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बारस्कर रहेंगी और उपाध्यक्ष महेश राठौर की भी गरिमामय उपस्थिति होगी।

भूमिपूजन कार्यक्रम का आयोजन क्रमशः तीन चौराहों पर किया जाएगा। सबसे पहले शाम 4 बजे शिवाजी चौक पर भूमिपूजन होगा। इसके बाद शाम 4:30 बजे कारगिल चौक पर और अंत में शाम 5 बजे अंबेडकर चौक पर भूमिपूजन किया जाएगा। इन तीनों प्रमुख चौराहों पर सौंदर्यीकरण के साथ-साथ पार्किंग निर्माण जैसे आवश्यक कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और चौराहा का सौंदर्य भी निखरेगा। इस योजना से बैतूल शहर का सौंदर्य और सुव्यवस्था दोनों बेहतर होंगे।

स्विफ्ट कार से 63 लीटर अवैध शराब जब्त, दो गिरफ्तार

बैतूल। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों को पकड़ा है। दरअसल बरेठा-घोड़ाडोंगरी मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक सफेद स्विफ्ट कार को रोका गया। कार से 63 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। कार में सवार बैतूल के दो युवक तनिष्क और नैतिक ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से देसी और विदेशी शराब की 7 पेटियां मिलीं। बरामद शराब और वाहन की कीमत करीब 4.50 लाख रुपए है। आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों नर्मदापुरम से शराब लाकर बैतूल में बेचने वाले गिरोह से जुड़े हैं। इस गिरोह के अन्य संदिग्धों की पहचान कर ली गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर के आदेश और जिला आबकारी अधिकारी अंशुमान सिंह चढ़ार के निर्देशन में की गई। टीम में आबकारी उप निरीक्षक गौरव पाण्डेय, सुरेन्द्र कुमार देवांगन, पूजा मालवीय और अन्य कर्मचारी शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

वायजी किंग रेस्टोरेंट से 6 किलो संदिग्ध मांस बरामद

फोरेंसिक जांच के लिए मथुरा भेजा सैंपल, दो गिरफ्तार

बैतूल। वायजी किंग रेस्टोरेंट के किचन से पुलिस ने 6 किलोग्राम संदिग्ध मांस बरामद किया है। रात साढ़े 11 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में गौमांस पकाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल एन. झारिया द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्रीमती शालिनी परस्ते के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस टीम ने फूड इंस्पेक्टर संदीप पाटिल एवं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल चौहान की उपस्थिति में घटनास्थल पर दबिश दी। मौके पर रेस्टोरेंट किचन से लगभग 6 किलोग्राम मांस बरामद हुआ, जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर प्रथक से सैम्पल लेकर फॉरेंसिक जांच हेतु मथुरा (उत्तर प्रदेश) की प्रयोगशाला भेजा गया। शेष मांस को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान समीर खान पिता जहीर खान, उम्र 32 वर्ष, निवासी पुराना बैल बाजार, छिंदवाड़ा और अनुपम पिता जॉन रॉबर्ट, उम्र 35 वर्ष, निवासी मोतीढाना चर्च कंपाउंड शाहपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सैम्पल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाही में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, फूड इंस्पेक्टर संदीप पाटिल, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल चौहान, नायब तहसीलदार जी.डी. पाठे, सउनि अजय अजनेरिया, प्र.आर. तरुण पटेल, प्र.आर. शुभम चौबे, महेश, प्रदीप, अमरदास, कमलेश, चंद्रपाल की सराहनीय भूमिका रही।

बुधवार को जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ

बैतूल। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा आज 11 जून बुधवार को अपराह्न 4 बजे शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे व बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी में खादी वस्त्रों एवं विंध्यावेली उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

किसान संगठनों ने कहा- सरकार समर्थन पर जल्द करे मूंग खरीदी, नहीं तो करेंगे आंदोलन

मूंग की खरीदी पर अनिश्चितता, मंडी में समर्थन मूल्य से भी कम रेट पर बेचने को मजबूर किसान

बैतूल। सरकार ने मूंग के समर्थन मूल्य में खरीदी को लेकर अभी तक तारीख घोषित नहीं की गई है। इससे जिले के हजारों किसान नुकसान झेल रहे हैं। जिसे लेकर मंगलवार को किसानों ने तहसील स्तर पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल समर्थन मूल्य में खरीदी को लेकर तारीख घोषित नहीं हुई है और मंडी में भी किसानों को मूंग के अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे है। ऐसे में किसान पशोपेश में हैं कि मूंग बेचें या नहीं। मंडी में मूंग के दाम 6 से 7 हजार रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। किसान पंजीकृत व्यापारियों को मूंग बेचने पर करीब डेढ़ से दो हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस साल समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं हो रही है। मजबूरी में कम दाम पर मंडी में फसल बेचनी पड़ रही है। मंगलवार को मंडी में 190 बोरे मूंग की आवक हुई। बता दे कि इस बार बडी संख्या में किसानों ने ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी की थी। किसानों को अच्छा उत्पादन भी हुआ। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए कृषि विभाग ने लगभग 20 हजार हेक्टेयर रकबा लक्षित किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में बड़े स्तर पर मूंग की बोवनी हुई थी। अब सभी किसान मायूस है कि उन्हें समर्थन मूल्य के बराबर मंडी में दाम नहीं मिल रहे है और समर्थन मूल्य में खरीदी को लेकर आदेश भी जारी नहीं हुए है।

मंडी में बड़ी मूंग की आवक- बडोरा मंडी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मंडी में मूंग की आवक लगातार हो रही है, जहां व्यापारियों ने क्वालिटी के अनुसार मूंग 5200 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल मूंग की खरीदी की, वहीं आने वाले दिनों में मूंग की आवक और बढ़ने की संभावना है,

क्योंकि जिले के कुछ क्षेत्रों में मूंग की कटाई और थ्रेसर का काम चल रहा है। इधर किसानों का आरोप है कि शासन की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। जिससे वे व्यापारियों को औने-पौने दामों पर मूंग बेचने को मजबूर हैं। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा तो की, लेकिन जमीनी स्तर पर खरीदी की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। जिन किसानों की फसल तैयार है। वे मंडियों में लाकर औने-पौने दामों में मूंग बेचने को मजबूर हैं।

मूंग फसल बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे किसान- किसानों पर तिहरी मार पड़ रही है। मौसम साथ नहीं दे रहा है। फसल बचाने के लिए किसान जद्दोजहद कर रहे हैं। फसल खराब न हो, इससे बचाने के लिए वे जल्दीबाजी में मंडी में कम दामों में में भी भी फसल फ बेचने के लिए तैयार हो रहे हैं। मौसम की मार, सरकार की मार, और उत्पादन उम्मीद के मुताबिक नहीं निकलने के कारण किसान परेशान हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि मूंग खरीदी की तारीख जल्द घोषित की जाए ताकि किसानों को उपज का उचित दाम मिल सके। ऐसा न होने पर किसान संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

पिछले साल 8682 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा था मूंग- समर्थन मूल्य में उपार्जन को लेकर अभी कोई आदेश नहीं आया है, अभी किसान मंडी में कम दाम में मूंग की उपज बेचने के लिए मजबूर है। केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष 2024-25 में 8 हजार 682 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग की खरीदी की थी। इस बार खरीदी को लेकर कोई आदेश नहीं आए है। मंडी में किसानों को मूंग के दाम 6 से 7 हजार रूपए तक मिल रहे है। समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होने के कारण किसानों को एक से डेढ़ हजार रुपए प्रति क्विंटल नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू हो जाती तो किसानों को लाभ मिलता। मंडी में उपज के कम दाम मिलने से किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है।

कृषि उपज मंडी में मूंग की आवक

दिनांक	न्यूनतम	अधिकतम	आवक
2 जून	6710	7225	55 बोरे
3 जून	5301	5301	17 बोरे
4 जून	6200	7199	12 बोरे
5 जून	5500	6900	26 बोरे
6 जून	5000	6551	83 बोरे
9 जून	4000	6651	96 बोरे
10 जून	4000	6050	190 बोरे

इनका कहना है -

मूंग खरीदी को लेकर शासन स्तर से अभी तक कोई आदेश नहीं आए हैं। आदेश आने पर खरीदी की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

-आनंद बडोनिया,
उपसंचालक कृषि विभाग, बैतूल

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यशाला का शुभारंभ

राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश पर हुई विस्तृत चर्चा

बैतूल। वन विद्यालय कालापाठा बैतूल में 10 जून को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीपीसी जितेन्द्र कुमार भनारिया ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यशाला में जिले भर के ब्लॉक सह-समन्वयक और संकुल सह-समन्वयक शामिल हुए। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार कार्यशाला में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण, प्रचार प्रसार, अक्षरसाथी का चयन, परीक्षा पूर्व की तैयारी, मूल्यांकन और मॉडल सामाजिक चेतना केन्द्र से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला में जिले से विभिन्न शिक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जिनमें वि.खंड. शिक्षा अधिकारी बैतूल नवीन प्रहलादी, प्रभात पट्टन वि.खंड.

शिक्षा अधिकारी आशीष शर्मा, सहायक परियोजना समन्वयक राजेश तुरिया, लेखा वित्त अधिकारी गणेश प्रसाद सोनी, जिला सह-समन्वयक कुशलेश धाड़से, बीआरसी बैतूल दुर्गेश रघुवंशी, आमला बीआरसी मनीष धोटे, और ब्लॉक सह-समन्वयक राजेश झाड़े, गणेश देशमुख, संजय सूर्यवंशी, राजेश निरापुरे, प्रवीण नरवरे, सेवाराम गायकवाड़, मनीष हुरमाड़े, अजय लाल, कल्पनाथ भारद्वाज, श्रीमती निलिमा शर्मा शामिल थे। कार्यशाला का मंच संचालन नेमीचंद मालवीय ने किया।

मध्यप्रदेश विधानसभा मा. अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के अध्यक्षता में E-Vidhan की हाउस कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में मा. उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मा. संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मान सदस्य श्री अजय विश्नोई, श्रीमती रीती पाठक, श्री गौरव पारधी, MPSEDC एवं NIC के अधिकारी सहित विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री ए पी सिंह उपस्थित रहें।

जिला अभिभाषक संघ चुनाव में सभी 26 प्रत्याशी मैदान में डटे, किसी ने नहीं लिया नाम वापस

27 जून को होगा बैतूल जिला अधिवक्ता संघ चुनाव, सभी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल

बैतूल। जिला अभिभाषक संघ बैतूल के आगामी चुनाव 27 जून को संपन्न होंगे। मंगलवार 10 जून को चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन फार्म वापसी की अंतिम तिथि शाम 4 बजे निर्धारित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन मिश्रा, सहायक निर्वाचन अधिकारी महेश कुमार रावत, अरविन्द देशपांडे एवं राकेश पटेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 26 उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए अपने नामांकन प्रस्तुत किए थे, लेकिन अंतिम समय तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया।

इस प्रकार अब सभी 26 प्रत्याशी सीधे चुनावी मुकाबले में रहेंगे। अलग-अलग पदों के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में अध्यक्ष पद हेतु दो उम्मीदवार अजय सिंह चौहान और अशोक वर्मा (चौधरी) मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए अलका गहीर, राजेन्द्र कुमार बघेल और सुनील कुमार बांसल (अग्रवाल), सचिव पद हेतु अजय सोनी, बलदेव कुमार महाजन, राजेश मंदरे, सहसचिव पद के लिए बंटी, दीपक कुमार आसरेकर और गौरव मगरदे ने नामांकन भरा है। कोषाध्यक्ष पद हेतु मनोज कुमार डफरे और सौरभ परिहार आमने-सामने होंगे। पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए लोकेन्द्र शेषकर और शिवकुमार कापसे ने नामांकन भरा है। कार्यकारिणी सदस्य पद हेतु 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें अनिल कुमार राठौर, भवानी प्रसाद दीवान, दिनेश उइके, मनीष कुमार राठौर, मोनिका निरापुरे, नीलेश उसरेटे, पूरनलाल राठौर, राजेश भूमरकर, रोशन मगरदे, संतोष खातरकर और वीरेन्द्र कुमार तिवारी शामिल हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन मिश्रा ने बताया कि चुनाव निर्धारित तिथि 27 जून 2025 को विधिवत संपन्न कराया जाएगा। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगी।

कलेक्टर ने तहसीलदार, पटवारी को तत्काल सीमांकन कराए जाने के दिए निर्देश

जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने पर चिचोली जनपद सीईओ का काटा एक दिन का वेतन

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जनसुनवाई में संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। इस दौरान चिचोली जनपद सीईओ के जनसुनवाई में अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने एक दिन का वेतन काटे जाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में कुल 152 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय सीमा में गंभीरता पूर्वक निराकरण किए जाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अक्षत जैन ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी।

जनसुनवाई में ग्राम चिल्कापुर निवासी बुजुर्ग नत्थू ने आवेदन के माध्यम से बताया कि उनका खेत ग्राम गुदगांव में है। तहसीलदार को सीमांकन किए जाने के लिए एक साल पहले आवेदन दिया था, लेकिन अब तक सीमांकन नहीं हो पाया है। आवेदक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित तहसीलदार को तत्काल सीमांकन किए जाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार भैंसदेही तहसील के ग्राम जामुलनी निवासी रामरति द्वारा

मशीन से सीमांकन कराए जाने के आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने भैंसदेही तहसीलदार को सीमांकन किए जाने के निर्देश दिए। बैतूल तहसील के ग्राम बोरगांव निवासी सुरेंद्र मालवीय ने बताया कि वर्ष 2022 में भूमिका सीमांकन कराए जाने के लिए तहसीलदार बैतूल को आवेदन दिया था। 3 साल बाद भी सीमांकन नहीं हो पाया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित पटवारी को तत्काल सीमांकन कराए जाने के निर्देश दिए।

अवैध कब्जे को हटाए जाने के दिए निर्देश- भैंसदेही तहसील की रीमू लोखंडे ने कृषि भूमि पर जबरन बलपूर्वक किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए जनसुनवाई में आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने भैंसदेही एसडीएम को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। आमला निवासी मोहित कवडे ने अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने डीईओ को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। आमला तहसील के ग्राम केहलपुर निवासी प्रमिला पाल ने अनावेदक द्वारा भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग की। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने आमला तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। शाहपुर तहसील के ग्राम देशावाड़ी निवासी नत्थू ने सीमांकन कराए जाने की मांग की। जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने शाहपुर तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग- जनसुनवाई में बैतूल के लोहिया वार्ड निवासी संगीता चढ़ार और माचना नगर निवासी बालक अहाके ने शासन से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए आवेदन दिया, प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने रोजगार कार्यालय के संबंधित अधिकारी को प्रकरण की जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। मुलताई निवासी नवल किशोर ने नामांतरण किए जाने के लिए आवेदन दिया, जिस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने मुलताई तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। आमला निवासी सुखवंती ने आवेदन के माध्यम से अनावेदक द्वारा कृषि भूमि पर ट्रैक्टर के माध्यम से बुवाई कर अवैध अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की। प्राप्त आवेदन पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने आमला तहसीलदार को कृषि भूमि का सीमांकन कर प्रकरण का निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। इस प्रकार जनसुनवाई में आए अन्य आवेदनों का भी मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया।

आतंकवाद को समाप्त करने हेतु प्रतिबद्ध मोदी सरकार

उपलब्धि

सुरेश पचौरी

(लेखक, भारत सरकार में रक्षा उत्पादन, कार्मिक व संसदीय कार्य राज्यमंत्री रहे हैं)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धि 'ऑपरेशन सिंदूर' की कामयाबी है। इस कामयाबी का पूरा श्रेय भारतीय सेना को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण को एक माह पूरा होने जा रहा है। देशवासियों ने भारत की बहादुर सेना के अद्भुत पराक्रम को देखा है, लेकिन विपक्ष के कतिपय नेताओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह के प्रश्न उठाये जा रहे हैं वे न तो सामयिक हैं और न ही उनका कोई औचित्य दिखता है। जो प्रमुख प्रश्न उठाये जा रहे हैं, वे हैं: सीज फायर क्यों किया गया? क्या इस फैसले में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दबाव डाला? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कितनी सैन्य क्षति हुई? इस विषय में चर्चा हेतु संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये सवाल आज की परिस्थितियों में गैरवाजिब है। इन सारे सवालों के उत्तर उचित फोरम पर दिये जा चुके हैं।

पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकर, सी.डी.एस. एवं तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ लगातार बैठकें की, रणनीति बनाई, लक्ष्य निर्धारित किया और आतंकवादियों के सफाये का अभियान शुरू किया, जिसे 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया गया। 7-8 मई की रात को भारत की सेना ने पाकिस्तान में लगभग 100 किलोमीटर घुसकर लक्षित हमला किया जिसमें आतंकियों के नौ ठिकानों, उनके प्रशिक्षण शिविरों तथा पाक एयरबेस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने राफेल जेट, एससीएएलनी मिसाइलों तथा हैमर बमों का उपयोग करके केवल 22 मिनट में मिशन पूरा किया। वस्तुत: पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। यह सामान्य साहस की बात नहीं है। दूसरी ओर आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के अनेक नेताओं, उच्च अधिकारियों तथा पाक सेना प्रमुख के शामिल होने से फिर इसकी पुष्टि हो गई कि आतंकवादियों के पाक सेना से बहुत गहरे संबंध है।

यह भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का नतीजा है कि महज 3-4 दिन में पाकिस्तान घुटने पर आ गया और युद्ध रोकने की गुहार करने लगा।भारतीय सेना से गहरी मार खाने के बाद पाकिस्तान के डी.जी.एम.ओ. ने भारत के डी.जी.एम.ओ. से 10 मई 2025 को निवेदन किया और अंतत: भारत ने अपनी जबावी कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कतर देश की यात्रा के दौरान स्वयं कहा है कि मैं यह नही कहता कि मैंने मध्यस्थता की है। ट्रंप के कथन को लेकर भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेनाध्यक्षों ने जो सही वस्तुस्थिति बताई है, भरोसा उस पर ही किया जाना चाहिए। सी. डी. एस. श्री अनिल चौहान ने स्वयं कहा है कि इस युद्ध में भारत की एकतरफा जीत हुई है। सेना के शीर्ष नेतृत्व की बात ही युद्ध के संदर्भ में मानी जानी चाहिए। जहां तक संसदीय सत्र बुलाने की बात है, देश की सुरक्षा और युद्ध ऐसे संवेदनशील विषय हैं जिन पर सार्वजनिक चर्चा से यथासंभव बचना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर के कई सकारात्मक पक्ष सामने आये हैं। पहला है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूसरा, सटीक और पुख्ता इन्टेलिजेन्स, तीसरा, भारतीय सेना की प्रोफेशनल क्षमता और चौथा, देश की एकजुटता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में, फिर 13 मई को आदमपुर में और इसके बाद बीकानेर में भारतीय सेना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के प्रत्येक पहलू को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सेनायें सतर्क हैं। हम पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने इस बात को कई बार जोर देकर कहा है कि

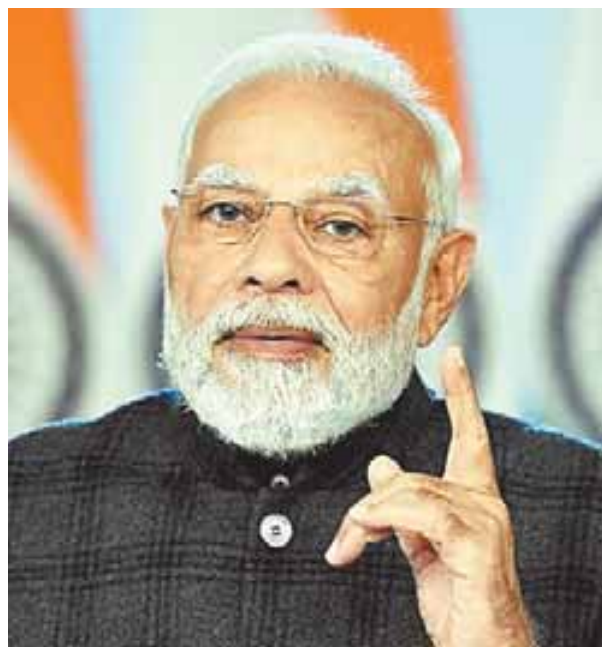

'ऑपरेशन सिंदूर' अभी जारी है, साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत, व्यापार और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चलेगा। अगर यह युग युद्ध का नहीं है तो आतंकवाद का भी नहीं है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नही हैं, इससे पूरी दुनिया त्रस्त है। प्रधानमंत्री की स्पष्ट घोषणा है कि भारत किसी भी परमाणु ब्लेकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। सीमा पर प्रोक्सीवॉर नहीं चलेगा। पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी, तो उसका एजेंडा आतंकवाद की समाप्ति एवं पीओके होगा। भविष्य में आतंकवादी घटनायें हुई तो उसे 'एक्ट ऑफ वॉर' मानकर ही कार्रवाई होगी। हम गोली का जबाब गोलों से देगें। प्रधानमंत्री के इस तरह दो टूक वक्तव्यों के बाद अब किसी को संदेह नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अनेक देशों में भेजा और उन सदस्यों ने जिस कुशलता से भारत का पक्ष रखा उससे उन देशों के मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। दूसरी ओर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सुश्री कनीमोजी, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी और असुद्दीन ओवेसी आदि पर कुछ लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर कांग्रेस के ही कुछ लोगों द्वारा उठाए जा रहे सवाल दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। स्मरणीय है कि 1994 में पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत को घेरने की रणनीति बनायी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानते हुए तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय प्रतिनिधि मंडल का मुखिया बनाकर जिनेवा भेजा था। अटल जी की बुद्धिमत्ता, उनकी तर्कपूर्ण पैरवी और नरसिंह राव जी की कूटनीति के सामने पाकिस्तान का झूठ टिक नहीं पाया। जो दायित्व देशहित में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्षी नेता के रूप में उस समय निभाया था, वही दायित्व अभी कांग्रेस के श्री शशि थरूर, जनाब सलमान खुर्शीद, श्री आनन्द शर्मा, श्री मनीष तिवारी ने निभाया है, और इन्होंने पाक को बेनकाब किया है। कांग्रेस के जो नेता अपने साथियों की प्रतिनिधि मंडल में भूमिका पर तरह-तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, यह अनुचित है, चूंकि पाकिस्तान इस तरह के वक्तव्यों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में उपयोग करता है।

यह भी याद रखना होगा कि 26 नवम्बर, 2008 को जब लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित आतंकवादियों ने मुंबई पर सबसे बड़ा हमला किया था जिसमें 160 से अधिक लोगों की जानें गयी थीं उस समय तत्कालीन सरकार ने क्या-क्या कार्रवाई की थी? आज जब ऑपरेशन सिंदूर पर अनावश्यक प्रश्न उठाये जा रहे हैं तो मुंबई हमले के बाद तत्कालीन सरकार की भूमिका से भी इसकी तुलना होगी।

भारत एवं पाकिस्तान की अनेक मायनों में कोई तुलना ही नहीं है। चाहे आर्थिक स्थिति का विषय हो या रक्षा तैयारी का मामला हो। पाकिस्तान भारत के समक्ष कहीं ठहरता ही नहीं है। भारत की कुल अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से 11 गुनी अधिक है। भारत की सैन्य क्षमता के मुकाबले पाकिस्तान अत्यंत कमजोर है। अभी तक हुये सभी पारंपरिक युद्धों में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। हमारे स्वदेशी रक्षा उत्पादन जैसे तेजस लड़ाकू विमान, ब्रम्होस मिसाइल,अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल अद्भुत हैं एवं भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात में लगभग 24,000 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया हैं। ऑपरेशन सिंदूर के एक माह पूरा होने पर यह नतीजा निकाला जा सकता है कि भारत आत्मरक्षा के मामलों में पूर्ण सक्षम है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में आतंकवाद को समाप्त करने हेतु भारत संकल्पबद्ध है।

जनपद पंचायत के प्रशिक्षु मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से सौजन्य भेंट कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया।

सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में होगा 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रधानमंत्री श्री मोदी का सपना और मुख्यमंत्री डॉ. यादव का संकल्प होगा पूरा : मंत्री शुक्ला

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश में वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट तक सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने में मध्यप्रदेश शत-प्रतिशत योगदान देगा। उन्होंने कहा कि भोपाल में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट में देश एवं प्रदेश के 350 से अधिक निवेशकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की है। सभी के उत्साह का ही परिणाम है कि योजना में 20 हजार करोड़ से अधिक राशि का निवेश होना संभावित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' समिट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्लोबल एक्सपर्ट एवं जेआईजेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री बर्नार्ड क्रूजबर को तकनीकी सहयोग के लिए सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक हैं। श्री मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रदेश में सोलर तथा पवन ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। मध्यप्रदेश के सोलर ऊर्जा उत्पादन से नई दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चल रही है और कई घरों को बिजली मिल रही है। निकट भविष्य में पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर 6-6 महीने बिजली उपलब्धता के लिए सोलर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल में राज्यों के बीच सौहार्द्र का वातावरण बना है। मध्यप्रदेश ने उत्तरप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ नदी जोड़ो परियोजनाएं शुरू की हैं। ऊर्जा

उत्पादन में नागरिकों को जोड़कर अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सूर्य अनंत ऊर्जा का भंडार है। सूर्य देव हमारे सौरमंडल में ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं। ऋषि-मुनियों ने बताया है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्रकाश से ही जीवन मिलता है। सनातन संस्कृति में सभी कार्यक्रमों की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से होती है, जो कि सूर्य आराधना का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना में छोटे-छोटे निवेशकों को भी जोड़ना एक सराहनीय प्रयास है। मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल में बड़े बदलाव आए हैं। मध्यप्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस है। मोहासा बाबई में नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण के लिए 22 इकाइयों का भूमि-पूजन किया जा चुका है इससे 24 हजार रोजगार सृजित होंगे। वर्ष 2025 तक प्रदेश के सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महेश्वर में बना फ्लोटिंग एनर्जी पार्क अद्भुत है। नीमच और रीवा में बड़े सोलर प्रोजेक्ट संचालित हैं। प्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 15 गुना बढ़ चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा में 48 प्रतिशत और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में राज्य में 9300 मेगावॉट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा की परियोजनाएं संचालित हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर बैंक सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी से किसानों की जीवन-शैली भी बदलेगी। सोलर एनर्जी से कोयला भंडार भी भरा रहेगा। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाते हुए बिजली के बिल से मुक्ति दिलाएगी। आगामी तीन वर्ष में 32 लाख सोलर पंप कनेक्शन लगाए जाएंगे।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा कि समिट के आयोजन से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सौर ऊर्जा में देश को अग्रणी बनाने के स्वप्न को पूरा करने में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश की ओर से किये जाने वाले अभूतपूर्व योगदान के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिशा और दशा को बदलने का कार्य हो रहा है। यह समिट 'सूर्य मित्र कृषि फीडर' योजना को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश में इस योजना में 1900 सब-स्टेशनों पर 100 प्रतिशत क्षमता तक की परियोजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जायेगा। योजना में निवेशकों को अपनी परियोजनाओं के लिये 1.5 करोड़ रूपये प्रति मेगावॉट का केन्द्रीय अनुदान चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। मंत्री श्री शुक्ला ने बताया कि देश में इस प्रकार की परियोजनाओं को रिएक्टिव पॉवर से संबंधित प्रोत्साहन देने का नवाचार प्रदेश में किया जा रहा है। यह योजना प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के मिशन को भी गति प्रदान करेगी। इसमें स्थानीय उद्यमियों के लिये निवेश एवं रोजगार सृजन के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे।

मंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि 'सूर्य मित्र कृषि फीडर' योजना में परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) में 7 वर्ष तक 3 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी। यह छूट निवेशकों को राहत देगी। उन्होंने बताया कि परियोजनाओं के विस्तार और कार्यान्वयन के लिये जर्मन सरकार की संस्था जीआईजेड से तकनीकी सहयोग भी लिया जा रहा है। मंत्री श्री शुक्ला ने कहा कि परियोजनाओं के लिये सुगम एवं व्यवस्थित वित्त पोषण को सुनिश्चित करने के लिये स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक और एयू स्मॉल बैंक इत्यादि से एमओयू हुआ है। निवेशकों को इन बैंकों के मार्फत फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में बिजली की कमी दूर करने के लिए ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। वे भावी पीढ़ियों के लिए कार्य कर रहे हैं इससे पर्याप्त बिजली और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ हमारा विभाग मिलकर कार्य कर रहा है। सोलर पंप लगने से किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार किसानों से अतिरिक्त बिजली भी खरीदेगी। बिजली से बचत की राशि स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर खर्च की जाएगी।

पीएम मोदी के 11 गौरवशाली वर्ष भारत के पुनर्जागरण, नव निर्माण और वैश्विक प्रतिष्ठा की यात्रा का प्रतीक : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने की यह अवधि केवल शासन के वर्षों की गणना नहीं, बल्कि भारत के पुनर्जागरण, नव निर्माण और वैश्विक प्रतिष्ठा की यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत में नेतृत्व का संकट, नीतिगत जड़ता और व्यापक निराशा का वातावरण था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को उस अंधकार से बाहर निकालकर एक नवउज्ज्वल, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर किया है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता' को विकास की मुख्य धारा में शामिल करते हुए, जन-कल्याण की योजनाओं को तीव्रता से धरातल पर उतारा। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, हर घर बिजली योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसे क्रांतिकारी प्रयासों ने सामाजिक संरचना को सशक्त और समावेशी बनाया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि देश में अब तक 58 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 7 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित की गई है। करोड़ों परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे उनका जीवन गरिमा और सुरक्षा से भर गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री मोदी का ही साहसिक नेतृत्व था, जिसने वर्षों से लंबित ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों को निर्णायक रूप से सुलझाया-चाहे धारा 370 का उन्मूलन हो, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं का अंत हो या संसद में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'विकसित भारत - 2047' का जो विज़न प्रस्तुत किया है, वह भारत को आने वाले वर्षों में जर्मनी, जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज भारत चौथे स्थान पर है, और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास उसके नेतृत्व में स्पष्ट दिखाई देता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के किसानों से मिलेंगे

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत कल बुधवार दिनांक 11 जून 2025 को किसानों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, उजवा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा की भागीदारी रहेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री दोपहर में तिगिपुर, बख्तावरपुर, उत्तरी दिल्ली में किसानों से बातचीत करेंगे। किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद होगा। उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री 'कृषि ड्रोन' के माध्यम से खेती में तकनीक के प्रयोग का अवकोलन करेंगे। तत्पश्चात पदयात्रा करते हुए किसानों से मिलेंगे और अंत में पौधारोपण के बाद मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों, अनुसंधान और सरकारी योजनाओं की उचित जानकारी पहुंचना है।

इस 15 दिवसीय महाभियान की शुरुआत 29 मई को ओडिशा से की गई थी। इस देशव्यापी अभियान के तहत श्री शिवराज सिंह चौहान ने अब-तक ओडिशा के बाद, जम्मू, हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में किसानों से संवाद किया है। इसी कड़ी में कल दिल्ली के किसान भाइयों-बहनों से मिलकर उनकी व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे।

खरीफ फसल में उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य के साथ 16 हजार वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से दो-तरफा संवाद कर रही है। एक तरफ उन्हें क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार, जलवायु परिस्थितियों, मिट्टी की उर्वरक क्षमतानुसार व अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि के लिए शोध की जानकारी दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर किसानों की व्यावहारिक समस्याओं व जरूरतों को भी सुनने और उनका समाधान निकालने के प्रयास हो रहे हैं ताकि भविष्य के कृषि शोध की दिशा और नीतियां तय की जा सकें।

एम्स भोपाल चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा

भोपाल। एम्स भोपाल के पैथोलॉजी लैब्स को 88 पैरामीटर्स के लिए प्रतिष्ठित एनएबीएल मान्यता प्राप्त एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, संस्थान निरंतर चिकित्सा अनुसंधान में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हाल ही में, एम्स भोपाल के पैथोलॉजी एवं प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग की प्रयोगशालाओं को 88 डायग्नोस्टिकमापदंडों के लिए ISO 15189:2022 मानकों के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से बहुप्रतीक्षित मान्यता प्राप्त हुई है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि डायग्नोस्टिक सेवाओं और रोगी देखभाल में एम्स भोपाल की उत्कृष्टता के प्रति सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रो. (डॉ.) अजय सिंह द्वारा गुणवत्ता और संस्थागत उत्कृष्टता की सतत खोज इस सफलता की आधारशिला रही है। इस अवसर पर प्रो. सिंह ने कहा, प्रत्यायन केवल एक प्रमाणपत्र नहीं है, बल्कि यह हर रोगी से एक वादा है कि उन्हें सटीकता, गुणवत्ता और वैश्विक मानकों पर आधारित सेवाएं मिल रही हैं।

राइट क्लिक

राहुल गांधी, कांग्रेस और नया राजनीतिक अश्वशास्त्र!

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस बात का श्रेय यकीनन देना पड़ेगा कि उन्होंने राजनीति के चरागाह में घोड़े, उनके प्रकार और सियासी ट्रीटमेंट को लेकर दिलचस्प बहस छेड़ दी है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि हाल के वर्षों में उन्होंने अश्वशास्त्र का बारीकी से अवलोकन किया है। पहले गुजरात और अब मप्र में उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस में राजनीतिक घोड़ों की पहचान कर उनके इलाज की संभावनाएं बताई और जगाई हैं, उसे आधुनिक भारत की राजनीतिक 'शालिहोत्रसंहिता' कहें तो गलत न होगा। 'शालिहोत्रसंहिता' ऋषि शालिहोत्र द्वारा रचित अश्वविज्ञान का प्राचीनतम ग्रंथ है। फर्क इतना है कि उन्होंने केवल प्राकृतिक घोड़ों के बारे में विवेचन किया है, जबकि राहुल गांधी ने 21वीं सदी की कांग्रेस में छिपे और प्रकट सियासी घोड़ों को आईडेंटीफाई करने और उनके इलाज पर अपना राजनीतिक मंतव्य प्रकट किया है। लेकिन राजनीति सहित हर क्षेत्र में घोड़ों से ज्यादा अहमियत उस पर सवार की होती है। सवार अगर मजबूत, सुलझा हुआ और साहसी हो तो घोड़ा भी रिस्क लेने में पीछे नहीं हटता। बेशक, राहुल ने घोड़ों की पहचान शुरू कर दी है, लेकिन क्या उनमें इतनी हिम्मत और प्रतिबद्धता है कि वो बेकाम और लंगड़े घोड़ों पर निर्ममता से चाबुक चला पाएंगे या फिर यह घोड़ेबाजी केवल बयानबाजी और चेतावनी तक ही सीमित है? क्या लंगड़े घोड़ों को बरतरफ करने से कांग्रेस का 'हॉर्सपावर' बढ़ेगा?

गौरतलब है कि घोड़े करीब 3 हजार से भी अधिक सालों से मनुष्य के न सिर्फ दोस्त रहे हैं, बल्कि मानव सभ्यता के हमसफर भी रहे हैं। युद्ध, परिवहन और रूआब में उनकी अहम भूमिका रही है। घोड़ा एक चतुर, समझदार, मेहनती और धैर्यवान प्राणी है। इनसे दो गुण कम गधे भी कम मेहनती नहीं होते, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से 'हानिकारक' नहीं माने जाते। या यूं कहे कि यदि किसी दल में घोड़ों की बहुसंख्या अगर उसे सत्ता के द्वार तक ले जाती है तो इसके विपरीत गधों की बहुसंख्या पार्टी को सदा संघर्ष के मोड में ही फंसाए रखती है।

वैसे अश्वशास्त्र के अनुसार मोटे तौर पर घोड़ों के तीन प्रकार होते हैं टट्टू, हल्के घोड़े और भारी घोड़े। जहां तक टट्टुओं की बात है तो हर सियासी पार्टी में इनकी बहुतायत होती है और जो पार्टी की महत्वाकांक्षा और हम्माली का बोझा ढोने और बदले में मामूली खुरचन पाकर भी संतुष्ट रहते हैं। नेताओं के जयघोष और उनके स्वागत में भीड़ जुटाना और छोटे मोटे ठेके, कमीशन आदि इनका मुख्य पेशा होता है। विचारधारा इनके लिए बूढ़ी माई की मानिंद होती है, जिसका अर्थ ठीक से समझे बगैर ये ताजिंदगी उसकी सेवा करते रहते हैं। इनकी तुलना तांगे के घोड़ों से की जा सकती है। दूसरी केटेगरी में हल्के लेकिन चपल घोड़ों होते हैं, ये ज्यादा जुगाडू और अवसरवादी होते हैं। समय की चाल को वक्त रहते भांप लेना, इन की खूबी है। ये रेस में दौड़ते हुए भी लेन बदल सकते हैं और मौका पड़े तो सत्ता की ट्रॉफी भी हथिया सकते हैं।

तीसरी श्रेणी उन भारी लेकिन दमदार घोड़ों की है, जो आम तौर पर सत्ता और संगठन के शीर्ष पर रहने के आदी होते हैं और वही जमे रहने की हिकमत जानते हैं। ये पीछे मुड़कर भी कम ही देखते हैं। खुद दौड़ने के साथ-साथ उपदेशों का चारा भी दूसरे घोड़ों को बांटते रहते हैं। बाकी घोड़े सर्वदा इनके कृपाकांक्षी रहते हैं। युद्ध में ऐसे राजसी मिजाज वाले घोड़े ही नेतृत्व करते हैं, भले ही उनका आम लोगों से राब्ता कम हो। लेकिन अब राहुल गांधी ने राजनीतिक घोड़ाशास्त्र की नई परिभाषा पेश की है। उनके मुताबिक भी कांग्रेस में तीन तरह के घोड़े पाए जाते हैं। 'रिसर्च पाइंट ऑफ व्यू' से यहां एक फर्क है। गुजरात दौरे तक राहुल गांधी ने कांग्रेसी घोड़ों की दो श्रेणियां नोट की थीं। लेकिन मप्र में 'संगठन सृजन अभियान' का शुभारंभ करते समय उन्होंने अनुभवजन्य एक श्रेणी और जोड़ी। यानी पहले कांग्रेस में रेस के और बाराती घोड़े ही थे। अब इनमें 'लंगड़े घोड़े' भी शुमार हो गए हैं। ऐसे घोड़े जो बरसों से कांग्रेस के रेस के घोड़े समझे जाते रहे, लेकिन अब उनकी तासीर फुंके हुए कारतूस सी है। जबकि बाराती घोड़े वो हैं, जो कांग्रेस के अच्छे दिनों में नाच कर गर्दिश के वक्त हरे-भरे चारागाहों में चले गए। इन्हें मौसमी घोड़े भी कहा जा सकता है। राहुल की इस थ्योरी के प्रेक्टिकल के तहत प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी ने केन्द्रीय मंत्री व पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाराती घोड़ा कह डाला तो उधर सिंधिया ने राहुल के 'लंगड़े घोड़े' को दिव्यांगों का अपमान बताया। इस बीच कांग्रेस में लंगड़े घोड़ों की मूर्तिमंत पहचान और उन्हें पार्टी से चलता करने की योजना पर मंथन चल रहा है। राहुल गांधी मानते हैं कि जब तक कांग्रेस के इन घोड़ों को ठीक नहीं किया जाएगा, उनका चंदी चारा दुरूस्त नहीं होगा, राजनीति की रेस में ट्रॉफी जीतने की जिद नहीं जागेगी, तांगे का घोड़ा बने रहने की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कांग्रेस का लवाजमा सत्ता के शाही जुलूस में तब्दील नहीं हो सकता। जब राहुल यह कहते हैं कि कांग्रेस बारात के घोड़ों को रेस में और रेस के घोड़ों को बारात में भेज देती है, तब यह सवाल पैदा होता है कि 'कांग्रेस' और इस अदूदरर्शी 'अदलाबदली' से उनका ठीक- ठीक आशय क्या है और क्या यह संज्ञा गांधी परिवार से अलग कोई चीज है? अगर दोनों तन-मन से एक ही हैं तो फिर सही घोड़ों की गलत तैनाती, काबिल घोड़ों के पार्टी से बहिर्गमन और लंगड़े घोड़ों के बेलगाम दौड़ते रहने के लिए जिम्मेदार कौन है? बेशक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उसकी मातृसंस्था आरएसएस पर बेखौफ हमले कर रहे हैं। वो उस संस्था को भी लपेट से नहीं चूक रहे हैं, जिसको वो संवैधानिक संस्था मानते हैं। इससे यह संदेश तो जा रहा है कि वो एक निर्भीक राजनेता हैं, लेकिन वो अपनी ही पार्टी रूपी अश्वदल के सक्षम अधिपति भी हैं, यह अभी सिद्ध होना है। दूसरे, कांग्रेस की मूल समस्या केवल घोड़े और उनकी काबिलियत ही नहीं है बल्कि पार्टी का एक अराजक अस्तबल में तब्दील होना भी है। कांग्रेस में अभी भी कई योग्य घोड़े हैं, जिन्हें सही दिशा, समर्थन और ऊर्जा की जरूरत है। वैसे भी हर घोड़ा सवार के इशारों पर दौड़ता है। शायद ही कोई घोड़ा अपने मन से रेस जीतने के इरादे से या फिर बारात में नाचने के लिए निकलता हो। कांग्रेस में घोड़ों की कितनी प्रजातियां हैं, इससे भी अहम बात यह है कि इन घोड़ों को अनुशासित और प्रतिबद्ध फौज में कौन और कैसे बदले? पूर्व में कांग्रेस में गुजरात में भी स्लीपर सेल की बात हुई। लेकिन उन पर कार्रवाई के लिए पार्टी को नींद से कौन जगाएगा, यह बड़ा सवाल है। भाजपा सत्ता के लिए हर संभव हथकंडे अपनाती हो, लेकिन वह स्पष्ट लक्ष्य के साथ काम करती है। राजनीतिक टट्टू वहां भी हैं, लेकिन घुडसवार अधिपति हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। यह सियासी चौकन्नापन कांग्रेस के अस्तबल में या तो नदारद है या बेहद कमजोर दिखता है। नेता की कमान में ताकत और जिगरा हो तो मरियल घोड़ों और टट्टुओं की फौज से भी सियासी किले जीते जा सकते हैं। कांग्रेस की असली समस्या अंतर्कलह, भयंकर गुटबाजी (घोड़ों में यह बुराई नहीं होती), अनुशासन की कमी, जीत का हार खुद गले में आ पड़ेगा की मानसिकता, समय पर फैसले न होना, हो भी गए तो उन पर अमल होते होते मौके का फिसल जाना, उत्सवी मानसिकता से काम करना, चुनाव के समय ही सक्रियता दिखाना आदि है। हालांकि अब इतने झटके खाने के बाद संगठन को कसने की बात हो रही है, तो अच्छा ही है। वास्तव में चुनाव टिकट पाने के लिए कांग्रेस के ये घोड़े जितनी मेहनत करते हैं, उसकी आधी भी गैर चुनावी मौसम में करें तो नया अश्वशास्त्र रचने की नौबत न आए।

संस्कृति पुरुष पं. सुरेश तातेड़ का निधन

भोपाल। राजधानी भोपाल में भारतीय संगीत की सांस्कृतिक परंपरा का सूत्रपात करने वाले संस्कृति पुरुष पं. सुरेश तातेड़ का मंगलवार अपराह्न 3 बजे दुखद निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे और विगत लगभग एक वर्ष से कैंसर से जूझ रहे थे। पाँच दिन पहले श्वास में तकलीफ के चलते बड़े चिकित्सा संस्थान में भर्ती कराया गया और जाँच में चिकित्सकों द्वारा हृदय की कार्यक्षमता 80 प्रतिशत समाप्त होना पाये जाने पर गहन हृदय चिकित्सा इकाई में उनकी चिकित्सा की जा रही थी । वे अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र अतुल तातेड़, एक पुत्री तथा भाइयों व नाती पोतों से भरा पूरा परिवार छोड़ गये हैं। उनकी अन्त्येष्टि कल की जायेगी। तातेड़ की जी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। वहीं आपने तबला वादन की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। सन 1963 में आपने भोपाल को अपनी कर्मभूमि बनाया और संगीत प्रेमी मित्रों के साथ मिलकर 'यूथ कल्चरल सोसायटी' नामक सांस्कृतिक संस्था का गठन किया जिसका नाम बदलकर बाद में 'अभिनव कला परिषद' कर दिया गया। संस्था अपनी सुरमयी यात्रा के 62 पड़ाव पार कर चुकी है। संस्था की सुदीर्घ संगीत सेवा हेतु उन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा 'राजा मानसिंह तोमर राष्ट्रीय सम्मान' प्रदान किया गया। 'सुबह सवेरे' की ओर तातेड़जी को श्रद्धांजलि।

विश्व नेत्रदान दिवस पर दूसरों के जीवन का अंधियारा मिटाने का लें संकल्प : मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के नागरिकों से आह्वान किया है कि वे दूसरों के जीवन का अंधियारा मिटाने के लिए नेत्रदान का संकल्प लें। नेत्रदान ही महादान है। नेत्रदान से दो व्यक्तियों की आंखों को भी रोशनी दी जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर कहा कि विश्व नेत्रदान दिवस हम सभी को प्रेरित करता है कि नेत्रदान, दुनिया से विदा होने के बाद भी मानव समाज की सेवा का अमूल्य माध्यम हो सकता है। उन्होंने कहा कि नागरिक अपने परिवार के सदस्यों और अन्य नागरिकों को भी नेत्रदान का महत्व बताते हुए ऐसा संकल्प लेने की प्रेरणा दे सकते हैं।

रेलवे वेंडर को गोली मारी

भोपाल (नप्र)। रेलवे वेंडरों के बीच लंबे समय से चल रही आपसी रंजिश मंगलवार देर रात हिंसा में बदल गई। बजरिया थाना क्षेत्र स्थित रेलवे अस्पताल के पास बीना से आए दो युवकों ने बाइक से जा रहे तीन वेंडरों पर पहले चाकू से हमला किया, फिर कट्टे से गोली चला दी। गोली एक युवक की टांग में घुटने के ऊपर जा लगी, जबकि दूसरे युवक को चाकू से घायल कर दिया गया। गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुराना विवाद बना हमले की वजह-टीआई जितेंद्र गुर्जर के मुताबिक, घायल युवक मनीष बुंदेला (21) रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है और रेलवे में वेंडर का काम करता है। उसके साथी राहुल और सलमान भी रेलवे वेंडर हैं। तीनों मंगलवार रात ट्रेन में काम निपटाने के बाद घर लौट रहे थे। तभी रेलवे अस्पताल के पास बीना निवासी आरोपी राहुल सोनी और उसके साथी ने उनकी बाइक रोक ली। जैसे ही बाइक रुकी, आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान वेंडर राहुल को चाकू मार दिया, जबकि सलमान पर कट्टे से फायर किया। गोली सलमान के पैर में घुटने के ऊपर लगी।

बीना से भोपाल आने को लेकर था विवाद-पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों और घायलों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। बीना निवासी आरोपी पक्ष नहीं चाहता था कि यह लोग बीना तक ना जाएं। वहीं फरियादी की ओर से कहा गया था कि आरोपी और उसके साथी भोपाल न आएं।

कैंसर पीड़ित में किडनी से 10 गुना बड़ा ट्यूमर

इलाज के दौरान आया हार्ट अटैक, बीएमएचआरसी में सर्जरी कर महाधमनी से चिपके ट्यूमर को निकाला

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गैस पीड़ित 58 साल के कैंसर रोगी एक साल से किडनी से 10 गुना बड़े ट्यूमर के साथ कठिन जीवन जी रहे थे। उन्हें अपनी बीमारी का आभास अब तक नहीं था। उनका पेट बांई ओर से फूलता जा रहा था। कई बार दर्द भी होता था, ऐसे में वे पेन किलर खा लेते थे। धीरे-धीरे लक्षण गंभीर होते गए और यूरिन से खून आना शुरू हो गया। जिसके बाद वे इलाज के लिए भोपाल मेमोरियल अस्पताल पहुंचे। जांच में ट्यूमर की पुष्टि हुई। जो किडनी और उसकी नसों व महाधमनी से चिपका हुआ था। यह कैंसरग्रस्त भी था। इन कारणों से यह सर्जरी बेहद जटिल थी, जिसे बीएमएचआरसी के डॉक्टरों द्वारा सफलता पूर्वक पूरा किया है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी किडनी का इतना बड़ा ट्यूमर नहीं देखा। मरीज की हालत में अब काफी सुधार है और उन्हें बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

किडनी 22 बाय 18 सेमी की हो गई थी

बीएमएचआरसी के कैंसर सर्जरी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. सोनवीर गौतम ने बताया कि सामान्य किडनी का आकार 9 बाय 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ट्यूमर की वजह से कैंसर की वजह से किडनी 22 बाय 18 सेमी की हो गई थी। यह ट्यूमर हार्ट से शरीर के अन्य हिस्सों में रक्त का संचार करने वाली महाधमनी और अन्य नसों से चिपक गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन के दौरान नस के फटने और अधिक ब्लीडिंग का खतरा बना हुआ था। उन्होंने बताया कि कैंसर पेट में मौजूद लिम्फ नोड्स में भी फैल गया था। इन लिम्फ नोड्स को भी निकाल दिया, जिससे भविष्य में कैंसर के दोबारा होने की आशंका भी खत्म हो गई है।

इलाज के दौरान आया हार्ट अटैक

एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉ. सारिका कटियार ने बताया कि मरीज को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिसका इलाज भी किया गया। इसकी वजह से मरीज को खून पतला करने की दवाएं चल रही थीं। ये दवाएं शरीर में खून का थक्का जमने से रोकने का काम करती हैं। ऐसे में अधिक ब्लीडिंग होने पर स्थिति को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन हमारी कुशल टीम ने ऐसी किसी भी आशंका को नकार दिया। सर्जरी करने वाली टीम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सोनवीर गौतम, एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉ. सारिका कटियार, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ संध्या इवने, कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. कपिलकांत त्रिपाठी ,सीनियर रेजिडेंट डॉ. ऋषि के. आठ्या, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉ. आशीष वैद्य और सीनियर नर्सिंग आफिसर जगदीश श्रीवास्तव शामिल रहे। सर्जरी करने वाली टीम में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सोनवीर गौतम, एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉ. सारिका कटियार, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ संध्या इवने, कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. कपिलकांत त्रिपाठी,सीनियर रेजिडेंट डॉ. ऋषि के. आठ्या, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉ. आशीष वैद्य और सीनियर नर्सिंग आफिसर जगदीश श्रीवास्तव शामिल रहे।

धूम्रपान की वजह से कैंसर होने का अनुमान

डॉ. गौतम ने बताया कि मरीज बीते 15 सालों से बीड़ी पीते थे। साथ ही गुटखा भी चबाते थे। तंबाकू और धूम्रपान किडनी के कैंसर का एक बड़ा कारण है।

फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर साइबर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ाया

अलवर में पुलिस की कार्रवाई, एक नाबालिग भी शामिल

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राइम ब्रांच) के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाने वाले साइबर ठगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलवर (राजस्थान) से गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा है, जिनमें एक नाबालिग और दूसरा पीओएस एजेंट शामिल है। गिरोह ने सिम कार्ड के फर्जीवाड़े के जरिए यह फर्जी प्रोफाइल तैयार की थी, जिसका इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने और संभावित धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा था।

ऐसे हुआ खुलासा

शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचना दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त क्राइम ब्रांच भोपाल की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल तैयार की है। मामला गंभीर होने के चलते क्राइम ब्रांच ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और साइबर टीम ने जांच शुरू की। अपराध कायम कर मामला पंजीबद्ध किया गया।

ऐसे रची गई साजिश

जांच में सामने आया कि यह एक संगठित साइबर गिरोह है। गिरोह ने सबसे पहले एक नाबालिग लड़के के नाम पर सिम कार्ड एक्टिवेट कराया। इसके लिए पीओएस एजेंट बीरबल प्रजापत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर 1500 रुपए दिए और उससे सिम एक्टिवेट करा ली। बाद में यही सिम 3000 रुपए में एक साइबर ठग को बेच दी। इसी सिम के माध्यम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल चलाई जा रही थी। साइबर टीम ने तकनीकी जानकारी के आधार पर राजस्थान के अलवर जिले में दबिश दी और लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र से आरोपी बीरबल प्रजापत (40 वर्ष) और नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल कर लिया है।

धर्मांतरण का लालच देकर मजदूर को फंसाने की कोशिश

भोपाल में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस बैंक खातों की भी कर रही जांच

भोपाल (नप्र)। सुखीसेवनिया थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां रहने वाले मजदूर अनिल कुशवाह को एक पुराने परिचित ने पैसों और दुकान का लालच देकर धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी कालूराम गौंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, अनिल कुशवाह मूलतः मजदूरी करता है और सूखीसेवनिया में रहता है। एकता नगर निवासी कालूराम गौंड फर्नीचर का काम करता है और उसकी अनिल से पहले से जान-पहचान थी। इसी का फायदा उठाते हुए कालूराम ने अनिल से कहा कि यदि वह ईसाई धर्म अपनाता है, तो उसे 50 हजार रुपए और एक किराने की दुकान खुलवाकर दी जाएगी। इससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और उसे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी।

अनिल ने किया इंकार, पहुंचा पुलिस के पास

अनिल कुशवाह ने कालूराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सीधे सूखीसेवनिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि आरोपी कालूराम गौंड स्वयं जनजातीय समुदाय से है और संभवतः उसका भी धर्मांतरण किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि कालूराम अकेला नहीं है, बल्कि वह किसी नेटवर्क के लिए काम कर रहा है जो भोले-भाले लोगों को पैसों का प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है।

चूंकि आरोपी ने 50 हजार रुपए और दुकान देने का लालच दिया था, पुलिस अब उसके बैंक खातों और लेन-देन की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे किसी संगठन या समूह का हाथ हो सकता है, जो बाहरी फंडिंग के जरिए यह गतिविधि संचालित कर रहा है।

राजभवन में राज्यपाल के परिसहाय की विदाई और स्वागत का हुआ कार्यक्रम

भोपाल (नप्र)। राजभवन में नवीन पदस्थ अधिकारी का स्वागत, स्थानांतरित एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों की विदाई का संयुक्त समारोह आयोजित किया गया। स्थानांतरित एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को स्मृति प्रतीक के रूप में अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। समारोह में राज्यपाल के स्थानांतरित परिसहाय श्री शशांक को विदाई और नव पदस्थ परिसहाय श्री नरेन्द्र रावत का स्वागत किया गया। राजभवन सचिवालय में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी डॉ. राजकुमार जैन को सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। राजभवन के अधिकारी-कर्मचारियों ने उनके साथ कार्य के अनुभवों को साझा किया। दोनों अधिकारियों ने राजभवन कार्यकाल के दौरान सभी के सहयोग के प्रति आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव ने परिसहाय श्री शशांक के कार्यकाल के अनुभव को साझा करते हुए नई प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएँ दी।

विमुक्त एवं घुमन्तु समुदाय सर्वेक्षण की कार्यशाला आज

भोपाल(नप्र)। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद एवं राज्य शासन के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विमुक्त एवं घुमन्तु समुदाय के सर्वेक्षण के लिये एक दिवसीय कार्यशाला 11 जून 2025 को राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में होगी। कार्यशाला का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा करेंगे। कार्यशाला में विभागीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर भी उपस्थित रहेंगे।